

कीमतें और मौद्रिक प्रबन्धन

वैश्विक संकट के बाद विश्व की अर्थव्यवस्था जैसे-जैसे स्थिर होनी शुरू हुई, मुद्रास्फीति ने, विशेषकर तेजी से पुनरुत्थान करती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मुख्य चिंता के रूप में पुनः सिर उठाया है। इस समय, कीमतों पर बढ़ा दबाव वैश्विक और घरेलू दोनों स्तरों पर खाद्य वस्तुओं और ऊर्जा क्षेत्रों से पड़ रहा है। तथापि, इस दबाव का अन्य प्रमुख क्षेत्रों में पहुंचने का खतरा बढ़ गया है और इसे सक्रियता से कम किया जाना जरूरी है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में धीमे पुनरुत्थान के बावजूद 2010 के अंत में अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं विशेषतः तेल, खाद्य वस्तुओं, औद्योगिक साधनों और धातुओं की कीमतों का बढ़ना देखा गया है। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों ने भी असामान्य ठंड के मौसम के कारण थोड़े समय के लिए प्रति बैरल 90 अमरीकी डालर के स्तर को पार किया जिससे सरकार पर ईंधन की घरेलू कीमतों पर पुनर्विचार करने का दबाव पड़ा। नया स्फीतिकारी दबाव दिसम्बर 2010 में स्पष्ट देखा गया जब हेडलाइन थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति नवम्बर, 2010 में 8.1 प्रतिशत से बढ़कर 8.4 प्रतिशत हो गई। तथापि, अब यह कम होकर जनवरी, 2011 में 8.2 प्रतिशत के स्तर पर आ गई है। ईंधन के अलावा, धातु और खनिज की कीमतें भी घरेलू अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल रही हैं। विशेषतः खाद्य मुद्रास्फीति एक वर्ष से अधिक समय से अब तक दो अंकों में ही टिकी है, जिसका खामियाजा कल्याणकारी योजनाओं को भुगतना पड़ रहा है। मुद्रास्फीति को कम करने के उद्देश्य के चलते सतर्क रहने और उभरती स्थिति की मांग के अनुसार सकारात्मक कदम उठाने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। आने वाले समय में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा प्रसार को रोकने के लिए किए गए उपायों और आपूर्ति पक्ष की बाधाएं दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों के अनुरूप मुद्रास्फीति के कम होने की संभावना है।

कीमतें

नई डब्ल्यूपीआई श्रृंखला की मुख्य विशेषताएं

4.2 2004-05 आधार वाली नई डब्ल्यूपीआई श्रृंखला 14 सितम्बर, 2010 को जारी की गई थी। 676 वस्तुओं वाले एक प्रतिनिधिक वस्तु समूह का चयन किया गया है और नई श्रृंखला के लिए भारांश आरेख तैयार किया गया है। पुरानी श्रृंखला में भाव कोटेशन की कुल संख्या 1918 से बढ़ाकर नई श्रृंखला में 5482 की गई है जो थोक बाजारों में कीमतों का बेहतर प्रतिनिधित्व करती है। पुरानी श्रृंखला के क्षेत्र-वार भाव कोटेशन प्राथमिक समूह के मामले में 455 से बढ़ाकर नई श्रृंखला में 579 तथा विनिर्मित उत्पाद समूह के लिए 1391 से बढ़ाकर 4831 किए गए हैं। प्रमुख समूहों के लिए वर्तमान और नई श्रृंखला के भारांश आरेख और वस्तुओं की संख्या की तुलना सारणी 4.1 में दी गई है।

4.3 नई श्रृंखला के वस्तु समूह में शामिल की गई कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं ये हैं- प्राथमिक वस्तुओं में फूल, नींबू और

कच्चा पेट्रोलियम तथा विनिर्मित उत्पादों में आइसक्रीम, डिब्बाबंद मांस, पाम ऑयल, तैयार/शीघ्र तैयार होने वाला खाद्य पाउडर, मिनरल वाटर, कम्प्यूटर की लेखन सामग्री, चमड़े के उत्पाद, स्कूटर/मोटर साइकिल के टायर, पॉलिमर, पेट्रो-रसायन की मध्यवर्ती वस्तुएं, ग्रेनाइट, मार्बल, सोना और चांदी, निर्माण मशीनरी, रेफ्रिजरेटर, कम्प्यूटर, डिश एन्टेना, ट्रांसफार्मर, माइक्रोवेव अवन, संचार उपस्कर (टेलीफोन उपकरण), टीवी सेट, वीसीडी, वाशिंग मशीन, तथा ऑटो के पुर्जे।

थोक मूल्यों की सामान्य स्थिति

4.4 2009-10 के पूर्वार्ध के दौरान हेडलाइन वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति 2008-09 में दर्ज की गई कीमतों में तीव्र वृद्धि होने के कारण 0.36 प्रतिशत के स्तर पर काफी कम बनी रही। 2009-10 के उत्तरार्ध में आधार प्रभाव के घटने के साथ कृषिगत वस्तुओं की आपूर्ति की प्रतिकूल स्थितियों के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी देखी गई, जिसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति में तीव्र

सारणी 4.1 : संशोधित डब्ल्यूपीआई शृंखला में भारांश और वस्तुओं में हुए प्रमुख परिवर्तन

मदें	भारांश		वस्तुओं की संख्या		
	नई शृंखला (आधार : 2004-05)	पुरानी शृंखला (आधार : 1993-94)	नई शृंखला (आधार : 2004-05)	पुरानी शृंखला (आधार : 1993-94)	जोड़ी गई नई /संशोधित वस्तुएं
सभी वस्तुएं	100.00	100.00	676	435	417
प्राथमिक वस्तुएं	20.12	22.03	102	98	11
खाद्य वस्तुएं	14.34	15.40	55	54	1
खाद्य-भिन्न एवं खनिज	5.78	6.63	47	44	10
ईंधन और विद्युत	14.91	14.23	19	19	0
विनिर्मित उत्पाद	64.97	63.75	555	318	406
खाद्य उत्पाद	9.97	11.54	57	41	25
खाद्य-भिन्न उत्पाद	55.00	52.21	498	277	381

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वृद्धि हुई। इसके बाद, हेडलाइन डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति मार्च 2010 में 10.23 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई।

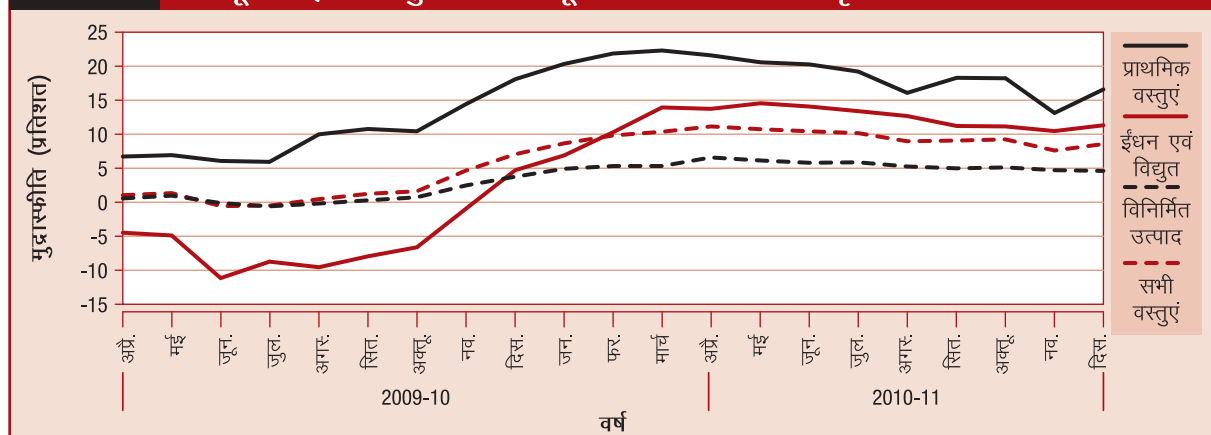
4.5 वित्त वर्ष 2010-11 की शुरुआत अप्रैल 2010 में हेडलाइन मुद्रास्फीति के 11 प्रतिशत के स्तर पर रहने के साथ हुई। 2010-11 के दौरान मानसून की स्थिति पिछले वर्ष की स्थिति से बेहतर रही है। दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2010-11 में खाद्यान्नों का उत्पादन पिछले वर्ष के 218.11 मिलियन टन के मुकाबले 232.07 मिलियन टन हो जाने की संभावना है। यद्यपि, मांग का दबाव शुरुआती 2010 में प्रकट हुआ।

4.6 पृथक-पृथक स्तर पर, तीन प्रमुख वस्तु समूहों की कीमतों का रूझान पिछले वर्ष के बिल्कुल विपरीत है जब विश्वभर में वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आने के कारण मुद्रास्फीति कम रही थी। मार्च से जुलाई, 2010 तक हेडलाइन मुद्रास्फीति दो अंकों में बनी रही। इसमें योगदान करने वालों में प्रमुख थीं-प्राथमिक वस्तुएं जिनकी मुद्रास्फीति 14.7 प्रतिशत से 21.5 प्रतिशत के बीच मंडराती

रही तथा ईंधन जिसकी मुद्रास्फीति 10.3 प्रतिशत से 14.4 प्रतिशत के दायरे में थी। हालांकि विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति चालू वर्ष के दौरान 4.5 से 6.4 प्रतिशत के अपेक्षाकृत छोटे दायरे में थी (चित्र 4.1)।

4.7 सरकार आम आदमी के लिए किफायती कीमतों पर रसोई ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। घरेलू ईंधन, नामशः केरोसिन और द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इन उत्पादों पर सब्सिडियां जारी रहेंगी। पीडीएस केरोसिन तथा घरेलू एलपीजी सब्सिडी योजना 2002 के साथ-साथ मालवहन सब्सिडी (दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए) योजना 2002 31 मार्च 2014 तक बढ़ा दी गई है। हालांकि अल्प-वसूलियों का भार कम करने के लिए दिल्ली में पीडीएस केरोसिन के खुदरा मूल्य में प्रति लीटर 3 रुपये और घरेलू एलपीजी की कीमत में प्रति सिलेंडर 35 रुपए की वृद्धि करने के साथ देश के अन्य भागों में तदनुसार वृद्धि

चित्र 4.1 डब्ल्यूपीआई के प्रमुख उप-समूहों में स्फीतिकारी प्रवृत्ति



करने का निर्णय लिया गया है। रिफाइनरी गेट और खुदरा स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बाजार द्वारा निर्धारित होंगी। तथापि, यह प्रस्ताव है कि डीजल की कीमतों में की जाने वाली वृद्धि कुछ-कुछ समय के अंतराल पर की जाएगी ताकि गरीब और कमजोर वर्ग पर पड़े समग्र प्रभाव को कम किया जा सके। यह भी निर्णय लिया गया है कि तेलों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उच्च वृद्धि और अस्थिरता रहने की स्थिति में सरकार पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण में उचित तरीके से हस्तक्षेप करेगी।

डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में औसत प्रवृत्तियां

4.8 हेडलाइन डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति का दस वर्षीय औसत 2000-01 से 2009-10 तक 5.3 प्रतिशत के आसपास था; इस दशक में 2000-01, 2003-04, 2004-05, 2006-07 और 2008-09 में दशकीय औसत से अपेक्षाकृत अधिक मुद्रास्फीति रही थी। चालू वित्त वर्ष में, 9.4 प्रतिशत की औसत मुद्रास्फीति (अप्रैल-दिसम्बर 2010) भी दशकीय दर से बहुत अधिक थी। ईंधन में दस वर्षीय औसत मुद्रास्फीति लगभग 8.9 प्रतिशत के आसपास थी। इसका अधिकांश 2000-01 की मुद्रास्फीति के कारण था। वर्ष 2003-04, 2004-05, 2006-07 और 2008-09 में भी विनिर्मित उत्पादों में उच्च मुद्रास्फीति देखी गई जो मुख्यतः कच्ची सामग्रियों जैसे बुनियादी मिश्र धातु और धातु उत्पादों, गैर-धात्विक खनिज उत्पादों और मशीनरी तथा मशीन के औजारों की अधिक कीमतों के कारण थी। वर्ष 2008-09 पिछले तीन वर्षों से भिन्न था क्योंकि तीनों क्षेत्रों में मुद्रास्फीति ईंधन तथा वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय कीमतें अधिक होने के कारण उच्च बनी रही। वर्ष 2009-10 वैश्विक मंदी और प्रतिकूल मौसम के कारण एक असामान्य वर्ष था। इसके बावजूद, ईंधन में ऋणात्मक मुद्रास्फीति के कारण औसत मुद्रास्फीति 3.6 प्रतिशत थी। चालू वित्त वर्ष (2010-11) में, अप्रैल से दिसम्बर 2010 तक 9.4 प्रतिशत की समग्र औसत मुद्रास्फीति पिछले दस वर्षों में दर्ज मुद्रास्फीति में सर्वाधिक थी (सारणी 4.2)।

डब्ल्यूपीआई में खाद्य मुद्रास्फीति

4.9 खाद्य सूचकांक में दो उप-घटक होते हैं नामशः प्राथमिक खाद्य वस्तुएं और विनिर्मित खाद्य उत्पाद। डब्ल्यूपीआई में समिश्र खाद्य सूचकांक का समग्र भारांश 24.31 प्रतिशत है, जिसमें प्राथमिक खाद्य वस्तुएं 14.34 प्रतिशत भारांश और विनिर्मित खाद्य उत्पाद 9.97 प्रतिशत भारांश के साथ शामिल हैं। घरेलू अर्थव्यवस्था में मुख्य चिंता वर्ष 2010-11 के दौरान खाद्य मूल्य की मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि होना रही है। डब्ल्यूपीआई खाद्य मुद्रास्फीति फरवरी 2010 में 20.22 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने के बाद कम होकर दिसम्बर 2010 में 8.59 प्रतिशत के स्तर पर आ गई। इसके दो घटकों में से प्राथमिक खाद्य मुद्रास्फीति ने संशोधित श्रृंखला में

सारणी 4.2 : डब्ल्यूपीआई आधारित वार्षिक औसत मुद्रास्फीति दर

वर्ष	प्राथमिक वस्तुएं	ईंधन और विद्युत	(प्रतिशत)	
			विनिर्मित उत्पाद	सभी वस्तुएं
भारांश (%)	20.12	14.91	64.97	100
2000-01	2.8	28.5	3.3	7.2
2001-02	3.6	8.9	1.8	3.6
2002-03	3.3	5.5	2.6	3.4
2003-04	4.3	6.4	5.7	5.5
2004-05	3.7	10.1	6.3	6.5
पहली 5 वर्षीय औसत	3.5	11.9	3.9	5.2
2005-06	4.3	13.5	2.3	4.3
2006-07	9.6	6.5	5.6	6.5
2007-08	8.3	0.0	4.9	4.8
2008-09	11.0	11.6	6.2	8.0
2009-10	12.7	-2.1	1.8	3.6
दूसरी 5 वर्षीय औसत	9.2	5.9	4.1	5.5
दशकीय औसत	6.4	8.9	4.0	5.3
2009-10 (अप्रैल-दिस.)	9.8	-5.8	0.7	1.7
2010-11 (अप्रैल-दिस.)^अ	18.0	12.3	5.3	9.4

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय टिप्पणी: अ-अनन्तिम

फरवरी 2010 में 21.9 प्रतिशत की ऐतिहासिक ऊंचाई छू ली थी, जिसके बाद यह कम होकर नवम्बर 2010 में 9.4 प्रतिशत पर आ गई और एक बार फिर बढ़कर दिसम्बर 2010 में 13.6 प्रतिशत हो गई (सारणी 4.3)। हालांकि विनिर्मित खाद्य उत्पादों ने मुद्रास्फीति में गिरावट प्रदर्शित की है जो दिसम्बर 2009 में 19.3 प्रतिशत के स्तर से कम होकर दिसम्बर 2010 में 0.4 प्रतिशत पर आ गई। खाद्य वस्तुओं में प्याज, फल, अण्डे, मांस और मछली तथा दूध की कीमतों में तीव्र वृद्धि देखी गई लेकिन खाद्यान्नों की कीमतें बढ़िया मौसम के कारण कम बनी रही तथा इनकी वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति दिसम्बर 2010 में -2.6 प्रतिशत थी।

खाद्य मुद्रास्फीति के मुख्य संचालक

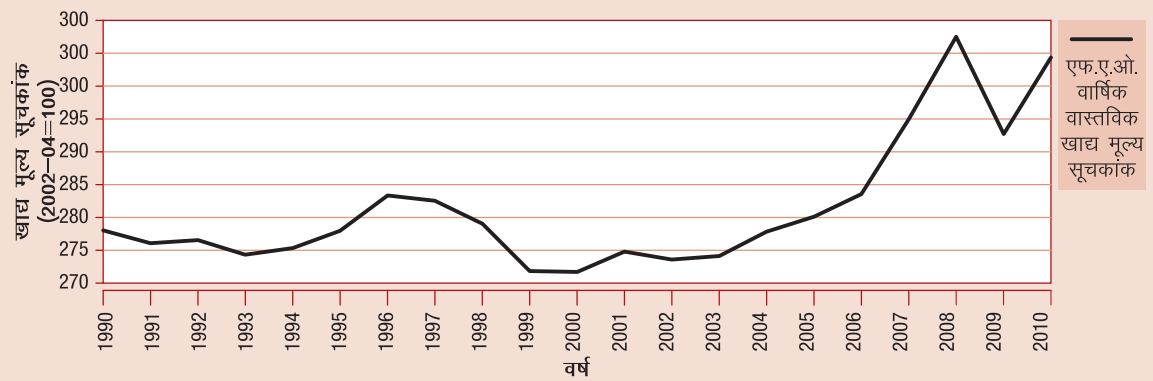
4.10 वर्ष 2010-11 में प्राथमिक खाद्य वस्तुओं में मुद्रास्फीति मुख्यतः चावल, सब्जियों, आलू, प्याज, फल, दूध, अण्डे, मांस और मछली, मिर्च-मसालों तथा चाय से संचालित थी। तथापि, 2004-05 के आधार वाली विनिर्मित खाद्य उत्पादों की डब्ल्यूपीआई संतोषजनक स्तर पर है। यह दिसम्बर 2009 में 142.2 प्रतिशत के मुकाबले दिसम्बर 2010 में 142.7 थी। यह वनस्पति तेल, मूंगफली के तेल, सूरजमुखी का तेल, चावल की खली के तेल, चाय और

बॉक्स 4.1: खाद्य मुद्रास्फीति में आया अप्रत्याशित उछाल

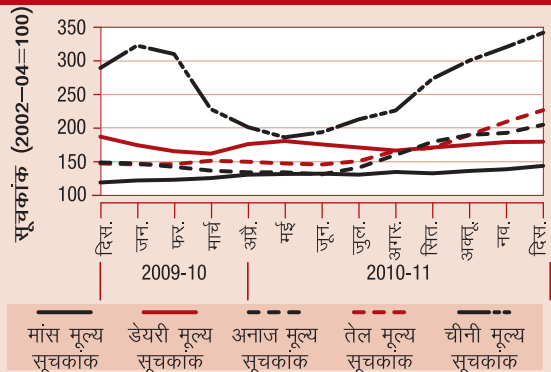
हाल के सप्ताहों में खाद्य मुद्रास्फीति अप्रत्याशित रूप से अधिक बनी रही है जो सब्जियों, फलों, डेयरी, तिलहनों और मसालों की कीमतों में आए उछाल के कारण है। इसकी उम्मीद नहीं थी क्योंकि 2010 में हुई अच्छी वर्षा हो जाने से कीमतें कम हो जाने की आशा थी। ऐसा हुआ भी: अनाज (गेहूँ, चावल) और दालों के मामले में, जिनसे भारत में परिवारों विशेषकर गरीबों द्वारा ली जाने वाली अधिकांश ऊर्जा और प्रोटीन मिलता है। किन्तु अन्य खाद्य पदार्थों की बेतहाशा बढ़ती कीमतों ने समग्र खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ाने का काम किया है। भारत की ऐसी पृष्ठभूमि में भोजन के अत्यधिक महत्व को देखते हुए—जहां कुपोषण की अधिक दर है और परिवार के कुल व्यय (धनी देशों में कुछ 7-8 प्रतिशत के मुकाबले) का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा भोजन पर खर्च किया जाता है—हम इस बॉक्स में कुछ प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय स्पष्टीकरणों अथवा कारकों के सापेक्ष महत्व की गुत्थी सुलझाएंगे।

- (1) **बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतें—मांग-आपूर्ति के झटके अथवा वस्तुओं की कीमतों में सामान्यीकृत उछाल?** 2006-08 में खाद्य की वैश्विक कीमतों में अचानक उछाल आया था, जो बाद में वैश्विक वित्तीय संकट के चलते लुढ़क गई थीं। तथापि, 2009 के लगभग अंत में कीमतें फिर से बढ़नी शुरू हुईं और चीनी, तेलों और वसा तथा अनाजों (डेयरी और मांस छोड़कर) की बढ़ी हुई कीमतों के कारण ये अब 2008 के सर्वोच्च स्तर से आगे जा चुकी हैं। इस वैश्विक वृद्धि को क्या प्रेरित कर रहा है? 2006-08 के पिछली मूल्यवृद्धि के आधार पर किया गया जुलाई 2010 का एक अध्ययन (बेफस और हेनिओटिस) में यह प्रमाण प्रस्तुत किया गया है कि यह वस्तुओं विशेषकर तेल की सामान्यीकृत मूल्य वृद्धि के कारण हुआ था जो स्वयं विश्वभर में आयी नकदी की बाढ़ और डालर के मूल्य में गिरावट आने से हुई थी। इसमें यह भी प्रमाण दिया गया है कि यह इनके (1) उभरते बाजारों (जैसे चीन और भारत) में बढ़ती मांग; (2) पारंपरिक ईंधन छोड़कर जैव-ईंधन की ओर मुड़ना और (3) प्रवृत्ति मूल्य की बढ़त (क्योंकि मूल्य में घट-बढ़ किसी भी प्रवृत्ति पर हावी होती है) के कारण नहीं था जैसाकि लोकप्रिय तर्क हमें विश्वास दिलाना चाहेंगे। तथापि, 1975 और 2001 के बीच वास्तविक खाद्य-मूल्यों में पूर्ववर्ती 53 प्रतिशत की गिरावट संभवतः बहुत अधिक थी और थोड़ा समायोजन करना आवश्यक हो गया था। 2009-10 की मूल्यवृद्धि भी बहुत कुछ इसी प्रकार की है। रूस में गर्मी के मौसम की गेहूँ की बहुत कम पैदावार से लेकर हाल ही में आस्ट्रेलिया में आई बाढ़, अर्जेंटीना में सूखा, इंडोनेशिया में बाढ़, अमरीका में मक्का की कम पैदावार और चीन और भारत में बढ़ती मांग तक सभी को दोष दिया जा रहा है—लेकिन इतने विविध खाद्य उत्पादों में अचानक इस हद तक हुई मूल्य वृद्धि का कारण विशिष्ट आपूर्ति अथवा मांग की समस्या को बता सकता कठिन है, सिवाय इसके कि यह वृद्धि वस्तुओं की सामान्यीकृत मूल्यवृद्धि (जिसका समाधान कहीं और है) के चलते हुई।

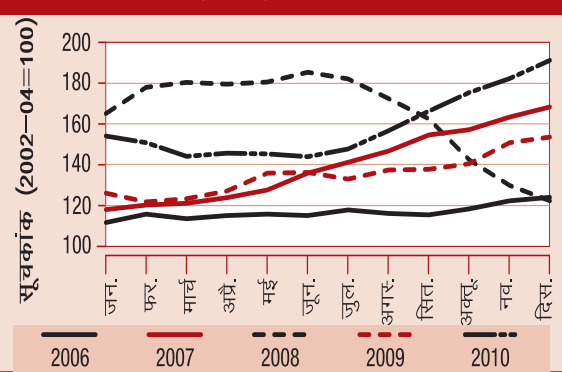
एफ.ए.ओ. वार्षिक वास्तविक खाद्य मूल्य सूचकांक



खाद्य वस्तु मूल्य सूचकांक



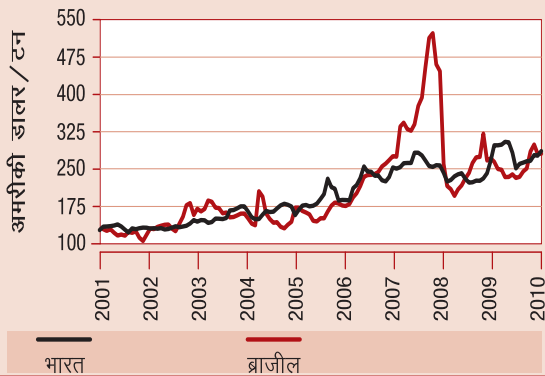
एफ.ए.ओ. खाद्य मूल्य सूचकांक



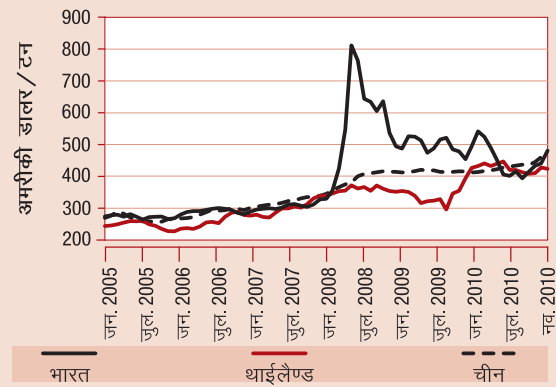
- (2) **क्या बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों से भारत को धक्का लगा है?** हालांकि वैश्विक कीमतों की कुछ आंच भारतीय बाजारों तक पहुंचना अवश्यभावी है, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बीच व्यापार और टैरिफ के अधिक अंतर के चलते कृषि में विश्व व्यापार अक्सर बहुत कम होता है। जहां खाद्य मदों की घरेलू कीमतों को वैश्विक कीमतों के असर से पूरी तरह बचाया नहीं जा सकता, स्थानीय बाजार कुछ भिन्न होते हैं, वैश्विक कीमतों में अस्थिरता घरेलू

(बॉक्स 4.1 जारी.....)

गेहूँ का थोक मूल्य: भारत और ब्राजील



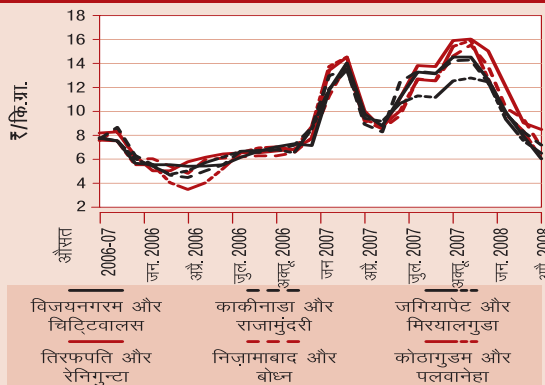
चावल का थोक मूल्य: भारत, थाईलैण्ड और चीन



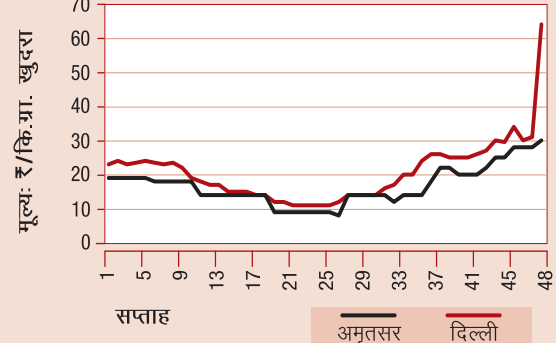
कीमतों के मुकाबले बहुत अधिक होती है, और भारत में कीमतें बहुत अधिक और बहुत कम से बचते हुए कहीं अधिक स्थिर रही हैं। सच तो यह है कि हाल में अनाज की कीमतें वैश्विक कीमतों की अपेक्षा भारत में गिरती रही है।

- (3) तो फिर, खाद्य-भिन्न वस्तुओं की कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि का क्या कारण है? बुनियादी सिद्धांत बनाम अप्रतिस्पर्द्धी बाजार। सब्जियों, मसालों, डेयरी और इसी तरह के उत्पादों की अचानक बढ़ती कीमतों के लिए एक लोकप्रिय तर्क यह है कि भारत में बढ़ती आय से कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि यह माना जाता है कि उपभोक्ता सस्ते उत्पाद न खरीद कर महंगे उत्पादों की ओर आकर्षित हो रहे हैं (एंगल के नियमानुसार)। हालांकि यह सामान्य मांग पक्ष के स्पष्टीकरण के तौर पर निश्चित रूप से सत्य हो सकता है, लेकिन दो अन्य कारकों के कारण इसकी गहन पड़ताल की जानी चाहिए, ये कारक हैं: (1) कीमतों में अचानक वृद्धि; और (2) ऐसे उत्पादों में आमतौर पर अधिक आपूर्ति की लोचशीलता जिससे यह रुक जानी चाहिए। इसके विपरीत, विश्वभर में जो कुछ नजर आ रहा है, उसके अनुरूप जब कुछ अनपेक्षित आपूर्ति अथवा मांग के झटके आते हैं, तो वस्तुओं की कीमतों में अस्थायी तौर पर वृद्धि होना अक्सर आसान होता है—जिनका बुनियादी सिद्धांतों के साथ कोई संबंध नहीं होता और ये कभी कभी स्थानीय उत्पादक संघों अथवा अन्य स्थितियों जैसे विरल वस्तु-वायदा बाजारों में सट्टा पूंजी के आकस्मिक प्रवाहों से प्रेरित होती हैं। प्याज की कीमतें पहले और मसालों की कीमतें दूसरे कारक का अच्छा उदाहरण हैं। प्याज की कीमतें कुछ ही सप्ताहों में प्रति किलो 15 रुपये से बढ़कर प्रति किलो 80 रुपये से अधिक हो गईं, जिसकी वजह सामान्यतः अधिक समय तक बारिश होना और नासिक में खराब फसल का प्रभाव कही जाती हैं। हालांकि असल में, प्याज भारत में उगाया जाता है, अखिल भारतीय बाजार आमतौर पर सुव्यवस्थित और प्रतिस्पर्द्धी है—जिसमें स्थानीय कीमतें राष्ट्रीय कीमतों के समाभिरूप हो जाती हैं। तथापि, अप्रत्याशित आपूर्ति अथवा मांग के झटके आने से स्थानीय प्याज बाजार बिखर जाता है और अधिक अराजकतापूर्ण हो जाता है तथा कीमतों में अचानक अस्थायी वृद्धि और भिन्नता देखी जा सकती है जो स्थानीय उत्पादक संघों की स्थितियों के अधिक अनुरूप होती है और जिसे आपूर्ति श्रृंखला में क्रमवार प्रवेश बाधाओं से मदद मिलती है। (जिसमें कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम (एपीएमसी) और मंडियों पर प्रतिबंध और शुल्क शामिल हैं)। तथापि, बुनियादी सिद्धांत अन्ततः सत्य सिद्ध होते हैं जैसाकि हाल के सप्ताहों में देखा गया है कि प्याज की कीमतें गिरकर प्रति किलो लगभग 25 रुपये रहीं और थोक बाजार में इससे भी कम हुई हैं। इसी प्रकार की स्थितियां कर्मांडी एक्सचेंजों पर लागू होती हैं जहां आकस्मिक सट्टा की गतिविधि वायदा कीमतों को अस्थायी तौर पर तक तब बढ़ा सकती हैं—जब तक आपूर्ति और बुनियादी सिद्धांत हाजिर मूल्यों और इस प्रकार वायदा कीमतों को फिर वास्तविक धरातल पर न ले आए। यहां तक कि सब्जियों की कीमतें भी, जिनमें नाटकीय वृद्धि देखी गई थी, आपूर्ति बढ़ने के चलते वापस कम हो रही हैं।

प्याज के खुदरा मूल्य की सुव्यवस्थित और समाभिरूप क्षेत्रीय श्रृंखला, आंध्र प्रदेश, 2006-2008

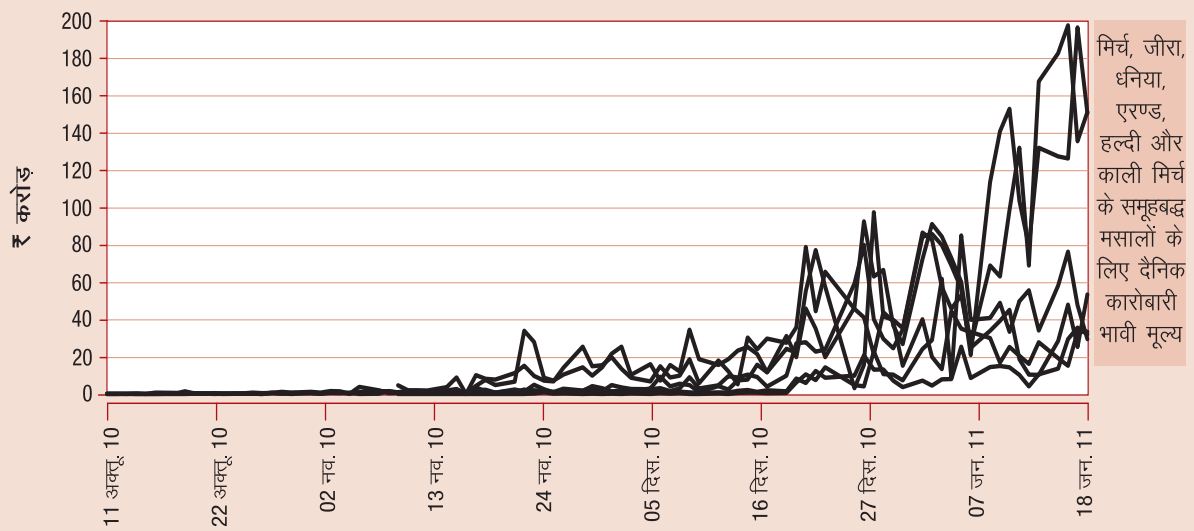


प्याज के साप्ताहिक खुदरा मूल्यों में अस्थायी रूप से कम "सुव्यवस्थित" घट-बढ़, उत्तर भारत, दिल्ली बनाम अमृतसर, दिसं. 2009-दिसं. 2010



(बॉक्स 4.1 जारी.....)

मसालों के दैनिक कारोबारी वायदा मूल्य में उछाल



संदर्भ: जॉन बैप्स और टेसस हेनिओटिस (2010), 'प्लेसिंग द 2006/08 कमोडिटी प्राइस बूम इन्टू पर्सपेक्टिव', पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर 5371, विश्व बैंक। फूड एण्ड एग्रिकल्चर आर्गेनाइजेशन (एफएओ), ग्लोबल फूड प्राइस मॉनीटर, 14 जनवरी 2011 एण्ड ग्लोबल इन्फार्मेशन एण्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम (जीआईईडब्ल्यूएस) कंट्री डाटा

सारण 4.3: डब्ल्यूपीआई खाद्य मुद्रास्फीति का मासिक ब्यौरा

(प्रतिशत)

भारंश %	सभी वस्तुएं		(क) खाद्य वस्तुएं		(ख) खाद्य उत्पाद		(क+ख) खाद्य संयुक्त	
	100	100	14.34	14.34	9.97	9.97	24.31	24.31
अवधि	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
अप्रैल	0.89	11.00	8.69	20.49	8.86	9.09	8.76	16.09
मई	1.21	10.60	8.91	21.37	10.12	7.09	9.37	15.85
जून	-0.71	10.28	11.28	20.97	9.05	6.13	10.42	15.30
जुलाई	-0.62	10.02	12.74	18.48	8.46	7.34	11.10	14.31
अगस्त	0.31	8.82	14.36	14.96	10.73	4.58	12.97	11.06
सितम्बर	1.09	8.93	13.92	16.29	12.08	3.62	13.21	11.49
अक्टूबर	1.48	9.12	12.47	14.64	12.97	3.75	12.66	10.56
नवम्बर	4.50	7.48 ^अ	16.73	9.41 ^अ	17.94	0.57 ^अ	17.17	6.11 ^अ
दिसम्बर	6.92	8.43 ^अ	20.76	13.55 ^अ	19.30	0.35 ^अ	20.21	8.59 ^अ
जनवरी	8.53		20.19		19.16		19.80	
फरवरी	9.68		21.85		17.68		20.22	
मार्च	10.23		20.65		15.11		18.50	

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

टिप्पणी: अ : अनन्तिम

सारणी 4.4: खाद्य मुद्रास्फीति के मुख्य संचालक

मदें	भारांश %	डब्ल्यूपीआई			वर्षानुवर्ष	वर्षानुवर्ष	* वित्तीय	वित्तीय
		दिसंबर 2009	मार्च 2010	दिसंबर 2010	मुद्रास्फीति 2010	भा०यो० 2010	वर्ष मुद्रास्फीति अप्रैल-दिसंबर 2010	वर्ष भा०यो० 2010
सभी वस्तुएं	100.00	132.9	135.8	144.1	8.43	100.00	6.11	100.00
प्राथमिक मदें	20.12	162.2	165.9	188.9	16.46	47.96	13.86	55.75
प्राथमिक खाद्य वस्तुएं	14.34	164.6	163.6	186.9	13.55	28.55	14.24	40.25
चावल	1.79	164.5	163.3	166.4	1.16	0.30	1.90	0.67
गेहूं	1.12	180.8	172.8	171.6	-5.09	-0.92	-0.69	-0.16
दालें	0.72	212.1	198.9	189.0	-10.89	-1.48	-4.98	-0.85
सब्जियां	1.74	180.0	132.0	224.9	24.94	6.96	70.38	19.43
आलू	0.20	240.1	105.4	176.3	-26.57	-1.15	67.27	1.72
प्याज	0.18	268.2	171.3	391.1	45.82	1.95	128.31	4.71
फल	2.11	136.0	145.6	163.8	20.44	5.23	12.50	4.62
दूध	3.24	151.0	167.2	178.5	18.21	7.95	6.76	4.41
अण्डे, मांस एवं मछली	2.41	164.3	172.1	195.9	19.23	6.81	13.83	6.92
मिर्च मसाले	0.57	202.7	204.9	270.6	33.50	3.45	32.06	4.50
चाय	0.11	165.8	129.1	156.7	-5.49	-0.09	21.38	0.37
विनिर्मित खाद्य वस्तुएं	9.97	142.2	141.7	142.7	0.35	0.45	0.71	1.20
चीनी	1.74	185.7	183.6	167.3	-9.91	-2.85	-8.88	-3.41
वनस्पति	0.71	107.3	108.5	119.6	11.46	0.79	10.23	0.96
मूंगफली तेल	0.30	133.0	131.5	147.8	11.13	0.40	12.40	0.60
सूरजमुखी तेल	0.17	115.8	112.5	128.4	10.88	0.20	14.13	0.33
चावल की खली का निष्कर्षण	0.09	210.3	210.4	231.2	9.94	0.17	9.89	0.23
चाय एवं काफी प्रक्रिया	0.71	148.6	140.7	160.4	7.94	0.75	14.00	1.69
मॉल्ट लिंकर	0.15	150.9	150.4	167.1	10.74	0.22	11.10	0.31

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

टिप्पणी : भा० यो०-भारित योगदान

काफी प्रक्रिया और मॉल्ट लिंकर के कारण मामूली सा बढ़ा है। सूचकांक में घट-बढ़ मुद्रास्फीति और खाद्य समूहों में हुई समग्र मुद्रास्फीति में उनका योगदान सारणी 4.4 में दर्शाया गया है।

4.11 मुख्य मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का वह पैमाना है जिसमें मूल्यों की अस्थिर घट-बढ़ वाली मदें शामिल नहीं हैं मुख्यतः खाद्य और ऊर्जा। इसलिए यह दीर्घावधि नीति तैयार करने के लिए एक वरीय साधन है। मुख्य मुद्रास्फीति, जो नवम्बर, 2009 में 0.55 प्रतिशत थी, बढ़कर अप्रैल 2010 में 8.07 प्रतिशत के अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई (सारणी 4.5)। तत्पश्चात, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किए गए मौद्रिक उपायों के कारण यह कम हो गई। तथापि, खाद्य-भिन्न विनिर्मित उत्पादों (भारांश 55.00 प्रतिशत) में मुद्रास्फीति अधिक नहीं बढ़ी थी और चालू वित्त वर्ष में यह 5.1 से 5.9 प्रतिशत के दायरे में रही। इसके बावजूद समिश्र खाद्य भिन्न सूचकांक (भारांश 75.7 प्रतिशत) में वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति अप्रैल 2010 में 9.18 प्रतिशत के स्तर से कम होती हुई सितम्बर 2010 में 7.9 प्रतिशत हो गई तथा फिर से बढ़कर दिसम्बर 2010 में 8.36 प्रतिशत हो गई।

4.12 खाद्य-भिन्न मुद्रास्फीति में चिन्ता की प्रमुख मदें हैं कपास, कच्चा पटसन, कच्चा रेशम, गरी, एरण्डी बीज, सूरजमुखी, कच्चा रबड़, तांबा अयस्क, जिंक, लौह अयस्क, सूती कपड़े, पेट्रो रसायन की मध्यवर्ती वस्तुएं और औद्योगिक मशीनरी और मशीनी औजार। डब्ल्यूपीआई में खाद्य-भिन्न घटकों के सूचकांक में घटबढ़ चित्र 4.2 में दर्शाई गई है।

4.13 ईंधन और विद्युत समूह की मुद्रास्फीति में बड़ा योगदान खनिज तेलों का है जो 90 प्रतिशत से भी अधिक बैठता है। (सारणी 4.6)।

विभिन्न मूल्य सूचकांकों के अनुसार वार्षिक मुद्रास्फीति

4.14 औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के संदर्भ में मुद्रास्फीति जुलाई 2009 से जुलाई 2010 तक दो अंकों में रही। कृषि श्रमिकों (सीपीआई-एएल) और ग्रामीण श्रमिकों (सीपीआई-आरएल)

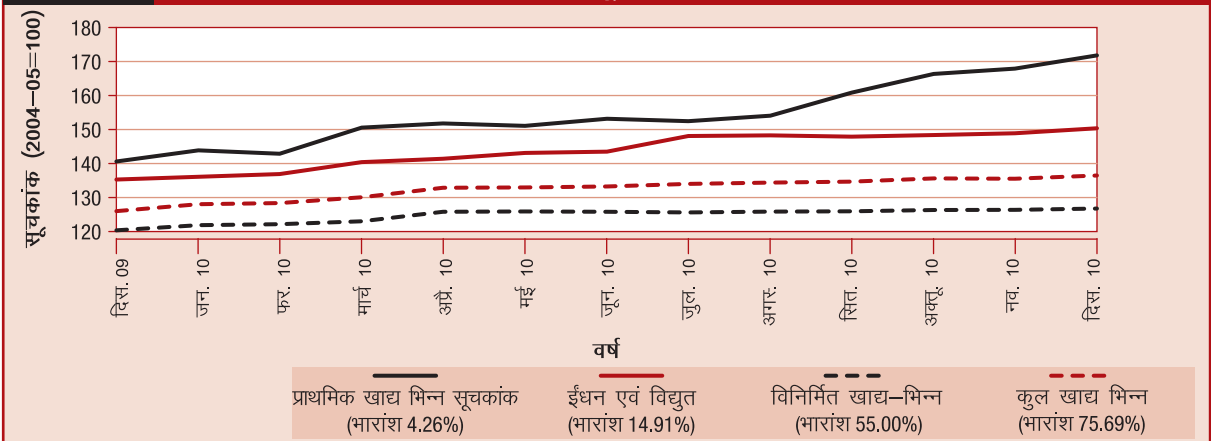
सारणी 4.5 2010-11 के दौरान डब्ल्यूपीआई खाद्य-भिन्न मुद्रास्फीति में घटबढ़

(प्रतिशत)

	संमिश्र खाद्य-भिन्न सूचकांक	खाद्य-भिन्न मदे	खनिज	ईंधन एवं विद्युत	मुख्य मुद्रास्फीति	खाद्य-भिन्न विनिर्मित उत्पाद
भारांश	75.69	4.26	1.52	14.91	60.78	55.00
अप्रैल 2010	9.18	18.08	34.56	13.61	8.07	5.92
मई-2010	8.71	14.76	25.34	14.42	7.27	5.77
जून-2010	8.47	15.83	22.08	13.92	7.09	5.55
जुलाई-2010	8.43	15.30	31.60	13.26	7.16	5.41
अग.-2010	7.97	15.81	23.77	12.55	6.77	5.21
सित.-2010	7.96	20.75	26.77	11.06	7.13	5.09
अक्टू.-2010	8.57	25.74	29.38	11.02	7.91	5.25
नव.-2010	8.02	23.22	21.54	10.32	7.40	5.41
दिस.-2010	8.36	22.31	27.69	11.19	7.60	5.34

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
टिप्पणी: मुख्य सूचकांक=कुल डब्ल्यूपीआई (कुल खाद्य+ईंधन एवं विद्युत)

चित्र 4.2 2010 के दौरान खाद्य-भिन्न डब्ल्यूपीआई में घट-बढ़



सारणी 4.6 ईंधन और विद्युत का सूचकांक तथा योगदान (समग्र मुद्रास्फीति से पृथक किया गया)

मदे	भारांश %	डब्ल्यूपीआई :2004-05=100			दिस. 2010/दिस. 2009		दिस. 2010/मार्च 2010	
		दिस. 2009	मार्च 2010	दिस. 2010	वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति	वर्षानुवर्ष भा.यो.	वित्तीय वर्ष मुद्रास्फीति	वित्तीय वर्ष भा.यो.
ईंधन एवं विद्युत	14.91	135.0	140.1	150.1	11.19	20.10	7.14	17.96
कोयला	2.09	162.7	163.0	163.0	0.18	0.06	0.00	0.00
खनिज तेल	9.36	138.6	146.6	160.5	15.80	18.31	9.48	15.68
विद्युत	3.45	108.6	108.6	114.0	4.97	1.66	4.97	2.25

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
टिप्पणी: भा.यो. भारत योगदान

के संदर्भ में मुद्रास्फीति मई 2009 में दो अंकों तक पहुंच गई थी और जुलाई 2010 तक ऐसे ही बनी रही। इसके अलावा, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के संदर्भ में मुद्रास्फीति इन सभी महीनों में सीपीआई-आईडब्ल्यू आधारित मुद्रास्फीति से अधिक थी। अगस्त 2010 में 15 महीनों में पहली बार सभी मूल्य

सूचकांकों के संदर्भ में मुद्रास्फीति कम होकर एक अंक पर आ गई है (सारणी 4.7)।

4.15 सीपीआई-आईडब्ल्यू में मुद्रास्फीति जनवरी 2010 में 16.22 प्रतिशत के अपने शिखर से काफी कम होकर दिसम्बर, 2010 में 9.47 प्रतिशत रह गई। पिछले वर्ष सीपीआई, डब्ल्यूपीआई

सारणी 4.7 : विभिन्न उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर आधारित वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति

महीना	डब्ल्यूपीआई (2004-05=100)		सीपीआई (आईडब्ल्यू) (2001=100)		सीपीआई (एएल) (1986-87=100)		सीपीआई (आरएल) (1986-87=100)	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
	अप्रैल	0.89	11.00	8.70	13.33	9.09	14.96	9.09
मई	1.21	10.60	8.63	13.91	10.21	13.68	10.21	13.68
जून	-0.71	10.28	9.29	13.73	11.52	13.02	11.26	13.02
जुलाई	-0.62	10.02	11.89	11.25	12.90	11.02	12.67	11.24
अगस्त	0.31	8.82	11.72	9.88	12.89	9.65	12.67	9.66
सितम्बर	1.09	8.93	11.64	9.82	13.19	9.13	12.97	9.34
अक्तूबर	1.48	9.12	11.49	9.70	13.73	8.43	13.51	8.45
नवम्बर	4.50	7.48 ^अ	13.51	8.33	15.65	7.14	15.65	6.95
दिसम्बर	6.92	8.43 ^अ	14.97	9.47	17.21	7.99	16.99	8.01
जनवरी	8.53		16.22		17.57		17.35	
फरवरी	9.68		14.86		16.45		16.45	
मार्च	10.23		14.86		15.77		15.52	
औसत अप्रैल-मार्च	3.57		12.37		13.91		13.76	

स्रोत: श्रम ब्यूरो, शिमला और आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
टिप्पणी ^अ : अंनतिम

की तुलना में ऊंचे स्तर पर रही जो मुख्यतः खाद्य वस्तुओं को दिए गए अधिक भारांश के कारण था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुएं डब्ल्यूपीआई में 24.31 प्रतिशत भारांश के योगदान के मुकाबले सीपीआई-आईडब्ल्यू में 46.20 प्रतिशत और सीपीआई-एएल में 69.15 प्रतिशत भारांश का योगदान करती हैं। खाद्य मुद्रास्फीति जनवरी, 2010 में अपने शिखर पर पहुंचने के बाद कम हो गई है। इसके परिणामस्वरूप सीपीआई मुद्रास्फीति दरें काफी कम हुई हैं।

उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के भिन्न-भिन्न रूप

4.16 इस तथ्य को देखते हुए कि अपेक्षाकृत उच्च मुद्रास्फीति का मौजूदा दौर खाद्य मर्दों, पान, सुपारी, तम्बाकू और मादक द्रव्यों और आवास पर केन्द्रित है, इस स्तर पर किए जाने वाले विश्लेषण का

महत्व बढ़ गया है। सीपीआई-आईडब्ल्यू मुद्रास्फीति को बढ़ाने में खाद्य मर्दों और आवास दो प्रमुख योगदानकर्ता हैं। खाद्य मर्दों और विविध समूह के बाद आवास क्षेत्र तीसरा बड़ा योगदानकर्ता है जिसका सीपीआई-आईडब्ल्यू के वस्तु समूह में 15.3 प्रतिशत का भारांश है। तथापि, औसत मुद्रास्फीति (अप्रैल-दिसम्बर 2010) पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में कम थी (सारणी 4.8)।

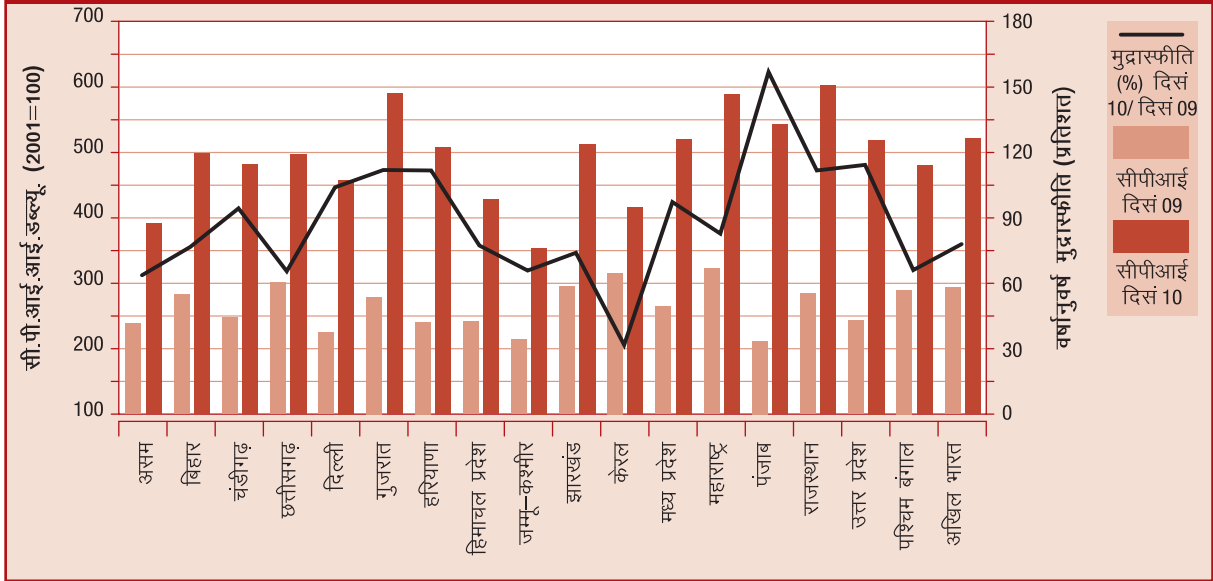
4.17 सीपीआई-आईडब्ल्यू में खाद्य-भिन्न मुद्रास्फीति अप्रैल-दिसम्बर 2010 के दौरान बढ़कर 11.64 प्रतिशत हो गई जबकि पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि में यह 8.78 प्रतिशत थी। अप्रैल-दिसम्बर 2010 के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि के 14.70 प्रतिशत के मुकाबले गिरकर 10.29 प्रतिशत रह गई (सारणी 4.8)। सीपीआई-आईडब्ल्यू में मुद्रास्फीति नवम्बर, 2010

सारणी 4.8 : मुख्य वस्तु समूह के अनुसार सीपीआई-आई डब्ल्यू में त्रैमासिक मुद्रास्फीति प्रवृत्ति (आधार : 2001=100)

सामान्य सूचकांक	भारांश	2009-10				2010-11			
		अप्रैल-जून-	जुलाई-सित.	अक्तू.-दिस.	अप्रैल-दिस.	अप्रैल-जून-	जुलाई-सित.	अक्तू.-दिस.	अप्रैल-दिस.
		100.00	8.87	11.75	13.06	11.67	13.66	10.31	9.16
खाद्य समूह	46.20	11.47	13.97	16.56	14.70	13.99	10.34	7.01	10.29
पान, सुपारी, तम्बाकू एवं मादक द्रव्य	2.27	7.44	8.80	7.86	8.34	12.93	12.13	11.26	12.10
ईंधन एवं प्रकाश	6.43	4.59	3.02	3.91	4.08	6.00	11.26	10.84	9.41
आवास	15.27	5.97	22.06	22.06	16.82	33.1	21.08	21.08	24.68
कपड़े, बिस्तर एवं जूते	6.57	4.14	4.38	4.22	4.34	4.51	5.51	7.05	5.70
विविध समूह	23.26	7.11	5.95	4.30	6.11	5.03	4.72	5.35	5.03
कुल खाद्य-भिन्न	53.80	6.45	9.64	9.62	8.78	13.33	10.27	11.42	11.64

स्रोत: श्रम ब्यूरो, शिमला

चित्र 4.3 दिसम्बर 2010 में प्याज की कीमत में घट-बढ़: राज्यवार सी.पी.आई. और वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति



के 8.33 प्रतिशत के मुकाबले बढ़कर दिसम्बर, 2010 में 9.47 प्रतिशत हो गई। सीपीआई-आईडब्ल्यू में भी खाद्य मुद्रास्फीति नवम्बर, 2010 में 5.35 प्रतिशत से बढ़कर दिसम्बर, 2010 में 7.98 प्रतिशत हो गई।

4.18 दिसम्बर, 2010 में सीपीआई-आईडब्ल्यू आधारित फल और सब्जियां तथा प्याज की मुद्रास्फीति क्रमशः 15.3 प्रतिशत और 77.6 प्रतिशत थी, जबकि डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति क्रमशः 22.77 प्रतिशत और 45.82 प्रतिशत थी। दिसम्बर, 2010 में प्याज की वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति और राज्यवार सीपीआई-आईडब्ल्यू उत्तरी क्षेत्र से विशेषरूप से पंजाब में मुद्रास्फीति में अभूतपूर्व वृद्धि को दर्शाता है (चित्र 4.3)।

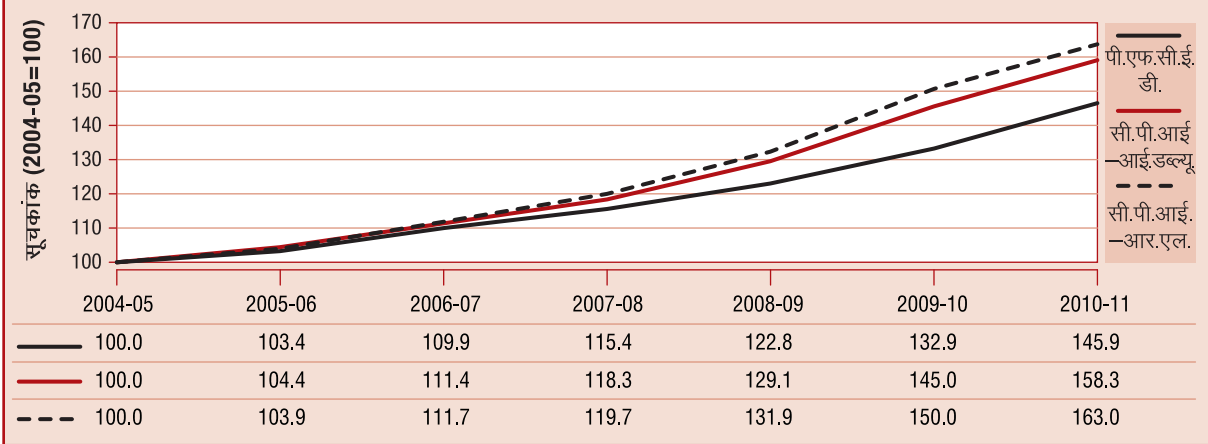
सीपीआई-शहरी और सीपीआई-ग्रामीण की शुरूआत

4.19 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए तथा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और समग्र भारत के सीपीआई (शहरी), सीपीआई (ग्रामीण) एवं सीपीआई (ग्रामीण+शहरी) को संकलित करने का नया काम शुरू किया है। ये सूचकांक शहरी और ग्रामीण जनसंख्या द्वारा इस्तेमाल की गई विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के रुख की सही तस्वीर दिखाएंगे। बाक्स 4.2 में सीपीआई (शहरी), सीपीआई (ग्रामीण) और राष्ट्रीय सीपीआई संबंधी एक संक्षिप्त छोटी टिप्पणी है जिसमें सूचकांकों की इस नई श्रृंखला की मुख्य विशेषताएं दी गई हैं।

बाक्स 4.2 : सीपीआई आंकड़ों की नई श्रृंखला

1. सीएसओ ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अखिल भारतीय स्तर पर अधिक कार्य क्षेत्र और कवरेज लिए हुए शहरी, ग्रामीण और संयुक्त (शहरी+ग्रामीण) सीपीआई की नई श्रृंखलाओं को संकलित करने का कार्य शुरू किया है।
2. सीपीआई (ग्रामीण) और सीपीआई (शहरी) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ-साथ अखिल भारतीय स्तर पर संकलित किया जाएगा। सूचकांकों के भारांश आरेख (उपभोग पैटर्न) उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (2004-05) के 61वें दौर के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के परिणामों के आधार पर बनाए गए हैं।
3. शहरी क्षेत्रों में, 9 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहर/नगर (2001 जनगणना) तथा इसके अन्तर्गत शामिल न होने वाले सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों की राजधानियों को सप्रयोजन शामिल किया गया था। कुल मिलाकर 310 शहरों को या तो प्रयोजनवश या फिर यादृच्छिक आधार पर चुना गया है जिनमें से 1114 कोटेशन (मूल्य अनुसूची) हर महीने मंगाई जाती है।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में, नियंत्रणीय कार्य भार को ध्यान में रखते हुए और यह विचारते हुए कि सीपीआई (ग्रामीण) देश की समस्त ग्रामीण जनसंख्या के लिए मूल्य में परिवर्तन की जानकारी मुहैया कराएगा, अखिल भारतीय स्तर पर कुल 1183 गांवों का चयन किया गया। गांवों के चयन का मुख्य मापदण्ड है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी जिलों का इसमें प्रतिनिधित्व होना और इस लिए राज्य व संघ राज्य क्षेत्र की ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक जिले से समायोजित विभिन्न तहसीलों में से दो गांवों को यादृच्छिक रूप से चुन लिया गया है।
5. सीएसओ ने एनएसएस के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (2004-05) आंकड़ों के 61वें दौर से तैयार किए गए उपयुक्त भारांश के साथ सीपीआई (शहरी) और सीपीआई (ग्रामीण) का विलय करके एक राष्ट्रीय सीपीआई बनाने का भी निर्णय लिया है।
6. मूल्य और निर्वाह व्यय संबंधी सांख्यिकी से संबंधित तकनीकी सलाहकार समिति ने 10 नवम्बर 2010 को आयोजित अपनी 49वीं बैठक में 2010 (जनवरी-दिसंबर) को नई सीपीआई (शहरी), सीपीआई (ग्रामीण) और सीपीआई (शहरी+ग्रामीण) श्रृंखला के लिए आधार वर्ष के रूप में मानने का निर्णय लिया है। जनवरी 2011 के सूचकांक फरवरी 2011 तक जारी किए जाने की संभावना है।

चित्र 4.4 मूल्य सूचकांक और पी.एफ.सी.ई.डी. की वार्षिक प्रवृत्ति



स्रोत: श्रम ब्यूरो और केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी: 2010-11 की पीएफसीईडी अग्रिम अनुमानों पर आधारित है, 2010-11 के सीपीआई-आईडब्ल्यू और सीपीआई-आरएल, अप्रैल-दिसम्बर 2010 की अवधि के लिए हैं।

निजी अंतिम उपभोक्ता व्यय अपस्फीतिकारक (पीएफसीईडी)

4.20 सकल घरेलू उत्पाद (स घ उ) अथवा सकल घरेलू आय (स घ उ) एक नियत अवधि में किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य होती है। इसे अक्सर सकारात्मक रूप से जीवन-स्तर से जोड़ा जाता है। देश की उपभोग संरचना में घट-बढ़ का विश्लेषण स्थिर मूल्यों के आधार 2004-05 की तुलना में वर्तमान कीमतों पर पीएफसीईडी द्वारा सृजित अपस्फीतिकारक के जरिए किया जा सकता है। 2004-05 से आगे सीपीआई-आरएल, सीपीआई-आईडब्ल्यू और पीएफसीईडी के वार्षिक मूल्य सूचकांक आंकड़े जीवन स्तर में वृद्धि का रुख दर्शाते हैं (चित्र 4.4)।

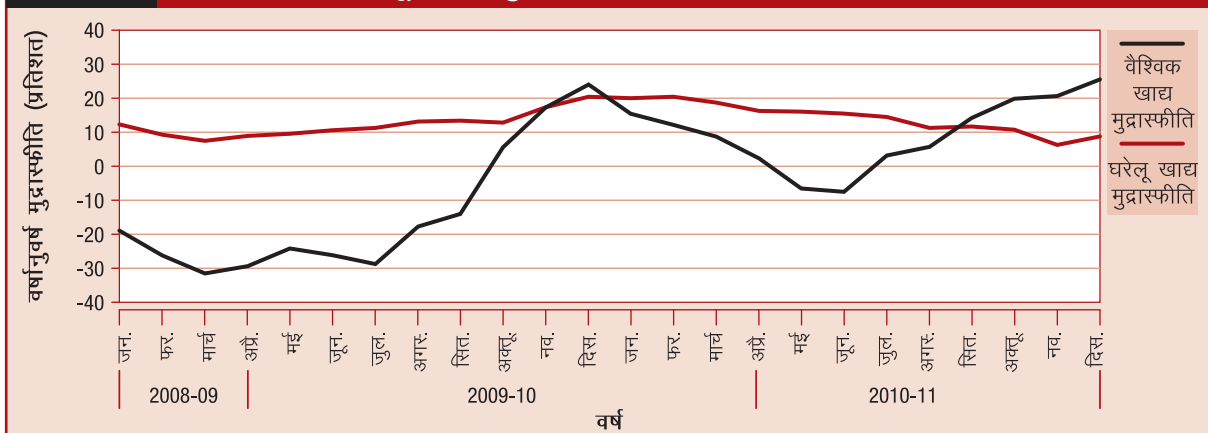
4.21 कीमतों में होने वाले परिवर्तन उपभोक्ताओं को एक चीज से दूसरी चीज खरीदने की तरफ मोड़ सकते हैं। जहां नियत वस्तु समूह वाले सीपीआई में कीमतों में होने वाले परिवर्तनों के कारण खरीदारी की आदतों में फेरबदल को शामिल नहीं किया

गया है वहीं ऐसी उप-स्थितियों को हिसाब में लेने की पीएफसीईडी अपस्फीतिकारक की क्षमता इसे मुद्रास्फीति का वरीय पैमाना बनाती है। सीपीआई-आरएल ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, जहां मूल्य सूचकांक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमएनआरजीएस) जैसी सरकार की रोजगार सृजन की विभिन्न योजनाओं के कारण क्रय शक्ति और खपत संरचना में सुधार होने के कारण सीपीआई-आईडब्ल्यू की तुलना में ऊंचे स्तर पर हैं।

वैश्विक और घरेलू मुद्रास्फीति

4.22 अप्रैल 2009 से वैश्विक खाद्य मूल्यों में डब्ल्यूपीआई आधारित घरेलू खाद्य मुद्रास्फीति के मुकाबले कहीं कम अस्थिरता देखी गई। तथापि, सितम्बर 2010 से भारत में घरेलू खाद्य मुद्रास्फीति के मुकाबले अन्तरराष्ट्रीय खाद्य मुद्रास्फीति में अधिक अस्थिरता देखी गई थी। अधिक महंगे आयात घरेलू मुद्रास्फीति को बढ़ा सकते हैं (चित्र 4.5 और सारणी 4.9)।

चित्र 4.5 वैश्विक और घरेलू खाद्य मुद्रास्फीति



सारणी 4.9 घरेलू और वैश्विक वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति (प्रतिशत)

(आधार: 2004-05=100)

वस्तु	घरेलू दिस.-09	वैश्विक दिस.-09	घरेलू मार्च-10	वैश्विक मार्च-10	घरेलू दिस.-10	वैश्विक दिस.-10
कृषि	18.5	28.5	20.6	17.8	15.3	27.8
पेय पदार्थ	6.5	27.8	8.2	23.0	5.3	32.4
ऊर्जा	4.6	55.4	13.8	60.1	11.2	19.7
वसा एवं तेल	-0.7	34.6	3.3	18.2	5.0	35.4
उर्वरक	7.0	-41.7	6.2	-27.1	5.5	39.6
खाद्य	20.2	23.8	18.5	8.5	8.6	25.3
अनाज	19.5	5.0	13.2	-10.3	-2.6	25.3
धातु एवं खनिज	-7.1	42.8	3.4	41.4	12.4	38.6
ईंधन-भिन्न	7.4	27.8	9.6	23.0	7.9	32.4
कच्चा माल	11.1	36.5	26.1	44.0	24.1	45.8
लकड़ी	-1.3	-9.2	8.8	-5.6	50.3	13.4
अन्य कच्चा माल	18.3	88.4	44.2	91.1	33.6	63.5
अन्य खाद्य	16.3	30.7	7.0	16.9	-0.5	10.2

स्रोत: पिक शीट, विश्व बैंक और आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

4.23 वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति और डब्ल्यूपीआई आधारित घरेलू खाद्य मुद्रास्फीति की तुलना खाद्य मुद्रास्फीति की सही तस्वीर पेश करती है। (सारणी 4.9)।

4.24 चालू वर्ष के दौरान, खाद्य वस्तुओं की अधिक मुद्रास्फीति सिर्फ भारत में ही नहीं हुई है बल्कि यह विश्वभर में व्याप्त है। घरेलू खाद्य तेलों जैसी कुछ खाद्य वस्तुओं के आयात पर निर्भर होने के कारण घरेलू खाद्य मूल्य स्थिति वैश्विक खाद्य मूल्यों में हुई वृद्धि के चलते बिगड़ सकती है। मौजूदा विकास और मुद्रास्फीति के रूझान मुद्रास्फीति रोधी मौद्रिक नीति के रूख को जारी रखना जरूरी बनाते हैं।

आवास मूल्य सूचकांक (एनएचबी-रेजिडेक्स)

4.25 विश्व में एक बहुत बड़ी जनसंख्या और सबसे तेजी से विकास करने वाले देशों में से एक होने के नाते प्रचुर विकास संभावनाओं के साथ गतिशील आवासीय बाजार के लिए भारत में आशाजनक स्थितियां मौजूद हैं। आवासीय क्षेत्र का राष्ट्रीय रोजगार में 9 प्रतिशत से भी अधिक का योगदान है। लेकिन भारत में आवास वित्त अभी अविकसित अवस्था में है। भारतीय आवास बाजार में चुनौती मुख्यतः कम और साधारण आय वाले क्षेत्रों में हैं। हालांकि आवास के लिए मांग में कोई कमी नहीं है, लेकिन ऋण प्रवाह कम हैं।

4.26 वर्ष 2007 में राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) ने पहली बार रेजिडेक्स की शुरुआत की ताकि विभिन्न शहरों और विभिन्न समयों पर भारत में आवासीय संपत्तियों की कीमतों का सूचकांक बनाया जा सके। शुरुआत में, आवासीय संपत्तियों की कीमतों में

हुए उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति को जानने के लिए 2001-05 के दौरान 2001 को आधार वर्ष मानते हुए एक प्रायोगिक अध्ययन किया गया। इस प्रायोगिक अध्ययन में पांच शहर नामशः बंगलौर, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई शामिल किए गए। तत्पश्चात् रेजिडेक्स के संकलन में दस और शहरों नामशः अहमदाबाद, फरीदाबाद, चेन्नई, कोची, हैदराबाद, जयपुर, पटना, लखनऊ, पुणे और सूरत शामिल किए गए। वर्तमान में रेजिडेक्स को 2007 के आधार वर्ष के साथ त्रैमासिक आधार पर अद्यतन किया जा रहा है। नवीनतम आंकड़ों में 15 शहर शामिल हैं और इन्हें जून 2010 (अप्रैल-जून) तक अद्यतन किया गया है।

4.27 2010 के पूर्वाह्न में एनएचबी रेजिडेक्स के अंतर्गत शामिल पंद्रह शहरों की आवासीय संपत्तियों से कीमतों के उतार-चढ़ाव में मिली-जुली प्रवृत्ति देखी गयी है। दस शहरों में आवासीय संपत्तियों की कीमतों में आधार वर्ष के मुकाबले वृद्धि का रुख देखा गया है। ये शहर हैं—सूरत, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, पटना, फरीदाबाद और भोपाल। तथापि, वे पांच शहर जिनमें 2010 के पूर्वाह्न में मूल्यों में सुधार देखा गया है, वे हैं जयपुर, बैंगलूरू, कोची, दिल्ली और हैदराबाद। जयपुर में आवासीय संपत्तियों के मूल्यों में अधिकतम सुधार देखा गया है (चित्र 4.6)।

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय

4.28 सरकार मूल्य स्थिरता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मूल्य स्थिति पर नियमित रूप से कड़ी नजर रखती है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों में

बॉक्स 4.3: मुद्रास्फीति विशेष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपाय

(क) मौद्रिक उपाय

मौद्रिक नीति की समीक्षा के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने मूल्य वृद्धि किए बिना विकास की रफ्तार को बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था की क्षमता के अनुरूप स्तरों तक मांग को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय किए हैं। इसने कई बार अपनी प्रमुख पालिसी दरों में वृद्धि की है और दरों में अस्थिरता कम करने के लिए नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) को संकुचित किया है। अर्थव्यवस्था में मार्च 2010 से आक्रामक मौद्रिक दुर्लभता देखी गई है। आरबीआई की 25 जनवरी 2011 की घोषणा के अनुसार, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर क्रमशः 6.5 प्रतिशत और 5.5 प्रतिशत है।

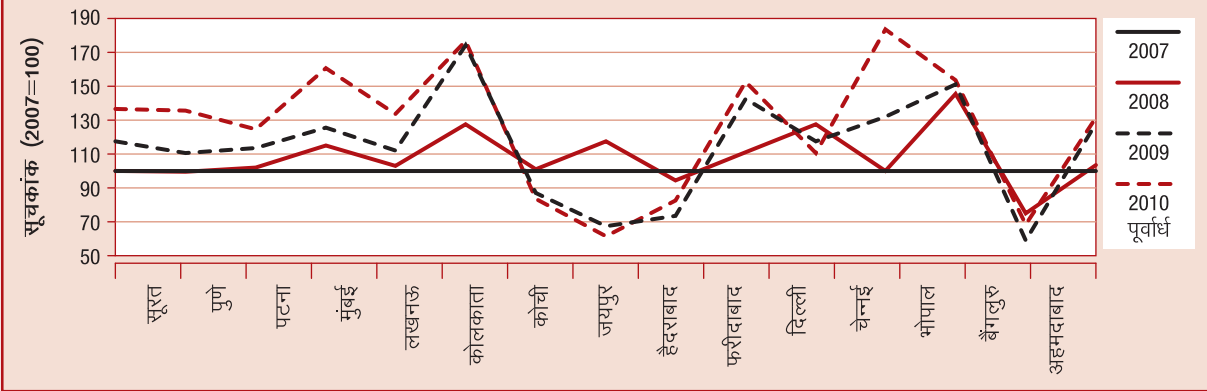
(ख) राजकोषीय उपाय

1. चावल, गेहूँ, दालों, खाद्य तेल (कच्चा), मक्खन और घी के मामले में आयात शुल्क घटाकर शून्य और परिष्कृत एवं हाइड्रोजनीकृत तथा वनस्पति तेल पर आयात शुल्क घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया गया।
2. कच्ची चीनी का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के तहत शून्य शुल्क पर किए जाने की इजाजत दी गई।

(ग) प्रशासनिक उपाय

1. समस्त आयातित कच्ची चीनी और सफेद/परिष्कृत चीनी के संबंध में लेवी संबंधी देनदारी हटा दी गई।
2. गैर-बासमती चावल, खाद्य तेलों (नारियल तेल और वन आधारित तेल को छोड़कर) और दालों (काबुली चना को छोड़कर) के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
3. प्याज (दिसंबर 2010 के लिए 1200 अमरीकी डालर प्रति टन) और बासमती चावल (900 अमरीकी डालर प्रति मी. टन) के निर्यात को विनियमित करने के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) तय किए गए।
4. वायदा बाजार आयोग द्वारा चावल, उड़द और तूर का भावी व्यापार आस्थगित किया गया।
5. स्टॉक सीमा संबंधी आदेश दालों, धान और चावल के मामले में 30 सितंबर 2011 तक और खाद्य तेलों एवं खाद्य तिलहनों के मामले में 31 मार्च 2011 तक लागू किए गए।
6. 22 दिसंबर 2010 से अगले आदेशों तक प्याज (सभी किस्में) का निर्यात किए जाने की अनुमति नहीं है।
7. 21 दिसंबर 2010 से प्याज और छोटी प्याज को बुनियादी सीमाशुल्क, विशेष अतिरिक्त शुल्क और शिक्षा कर से पूरी छूट दी गई।
8. नेफेड और एनसीसीएफ विभिन्न स्थानों पर स्थित अपने खुदरा केंद्रों पर 35 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर पर प्याज की बिक्री करेंगे जिसे उपयुक्त बजटीय सहायता दी जाएगी।
9. अधिक व्यापक कार्यक्षेत्र लिए अन्य उपाय इस प्रकार हैं:
 - क. किसान मंडियाँ और चलते-फिरते बाजार स्थापित करने और नागरिक पूर्ति निगमों एवं सहकारिताओं के कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों की मदद करने की एक योजना को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।
 - ख. मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को कम्प्यूटरीकरण एवं ऐसे उपायों के ज़रिए पर्याप्त मज़बूत बनाया जाएगा, जिनमें देश भर में अधिक अधिप्राप्त केंद्र खोलना शामिल है।
 - ग. राज्य सरकारों से एपीएमसी अधिनियमों की समीक्षा करने, विशेषकर बागवानी के उत्पादों को उनके कार्यक्षेत्र से छूट देने का अनुरोध किया जाएगा जिससे इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में विपणन और वितरण संबंधी अड़चनें दूर की जा सकें। राज्य सरकारों से मंडी कर, पथकर और अन्य स्थानीय करों जिनसे आवश्यक वस्तुओं की अबाध आवा-जाही में रोक लगती है, को माफ करने पर विचार करने और कमीशन एजेंट के प्रभावों को कम करने का अनुरोध किया जाएगा।
 - घ. आपूर्ति श्रृंखलाओं में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा तथा प्रशीतन भंडारों के लिए व्यवस्था की जाएगी, जिन्हें फार्म उत्पादों के अधिक शीघ्र और अधिक कार्यक्षम वितरण के लिए संगठित खुदरा श्रृंखलाओं के साथ जोड़ा जाएगा जिससे बर्बादी कम होगी। डीआईपीपी, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और योजना आयोग इस प्रयोजनार्थ स्कीमें तैयार करेंगे।
 - ङ. मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अन्तः मंत्रालयीय समूह (आईएमजी) गठित किया गया है जो प्राथमिक खाद्य वस्तुओं के विशेष संदर्भ में समग्र मुद्रास्फीति की स्थिति की समीक्षा करेगा। यह, आईएमजी अन्य बातों के अलावा उत्पादन/वर्षा की प्रवृत्तियों की समीक्षा करेगा और चेतावनी संकेत समझने के लिए संस्थागत तंग तैयार करेगा, अंतरराष्ट्रीय रूझानों का मूल्यांकन करेगा, मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए राजकोषीय, मौद्रिक, उत्पादन, विपणन, वितरण एवं अवसरचना के मोर्चों पर कार्रवाई करने की सिफारिश करेगा तथा आंकड़ों एवं पूर्वानुमानों के संग्रहण एवं विश्लेषण की व्यवस्था को मज़बूत बनाने के उपाय सुझाएगा।
 - च. मंत्रिमंडल सचिव के अधीन सचिवों की समिति अलग-अलग राज्यों के साथ मूल्य-स्थिति की समीक्षा करेगी तथा केंद्र सरकार के संबंधित विभागों को राज्य अधिकरणों के साथ निकट समन्वय बनाए रखने की सलाह देगी ताकि जल्दी से उपयुक्त सुधारात्मक उपाय करने के लिए सीधे ही जानकारी मिल सके।

चित्र 4.6 शहरवार औसत रेजिडेक्स में घट-बढ़



शामिल हैं- खाद्यान्नों के निर्यातों और वायदा कारोबार पर चयनात्मक प्रतिबन्ध, चुनिन्दा खाद्य वस्तुओं पर शून्य आयात शुल्क, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दालों और चीनी का आयात करने की अनुमति देना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयातित दालों और खाद्य तेलों का वितरण और गैर-लेवी चीनी का अधिक कोटा जारी करना। इसके अलावा, राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत लाइसेंसिंग, स्टॉक सीमाओं और खाद्य वस्तुओं की आवाजाही पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने को आस्थगित रखकर खाद्य वस्तुओं के जमाखोरों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है। आवश्यक कतिपय मुद्रास्फीति-रोधी उपाय बॉक्स 4.3 में दिए गए हैं।

2010-11 के दौरान मौद्रिक घटनाक्रम

4.29 सितंबर-मध्य 2008 से शुरू हुए वैश्विक वित्तीय संकट को लेकर की गई कार्रवाई के तौर पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति का ऐसा समायोजनकारी दृष्टिकोण अपनाया जिससे बाजार प्रतिभागियों में विश्वास पैदा करने और अर्थव्यवस्था का यथासंभव जल्द पुनरुत्थान सुनिश्चित करने में मदद मिली। भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2009-10 के दौरान पुनरुत्थान की रफ्तार में तेजी दिखाई। कमी वाले मॉनसून के बावजूद, वैश्विक संकट की अनुक्रिया स्वरूप अपनाए गए विस्तारकारी मौद्रिक और राजकोषीय दृष्टिकोण ने इस पुनरुत्थान में सहायता की। वर्ष के पूर्वार्ध के दौरान कुछ मंद पड़े रहने के बाद, उत्तरार्ध में हेडलाइन मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई जो आरंभ में उच्च खाद्य मूल्यों से प्रेरित थी लेकिन अनुवर्ती महीनों में अधिक सामान्यीकृत हो गई। बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति और सुदृढ़ होते पुनरुत्थान के साथ-साथ स्फीतिकारी संभावनाओं पर पड़नेवाले इसके प्रभाव के जोखिम को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने “संकट की प्रबंध-व्यवस्था” के दृष्टिकोण से हटकर “पुनरुत्थान की प्रबंध व्यवस्था” का स्पष्ट परिवर्तन लाने की बात कही और कुछ क्षेत्र-विशिष्ट सुविधाओं को समाप्त करके तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सांविधिक नकदी अनुपात (एसएलआर) को इसके संकट पूर्व स्तर पर बहाल करके अक्टूबर 2009 की दूसरी

त्रैमासिक समीक्षा में विस्तारकारी मौद्रिक नीति से हटने के पहले चरण की घोषणा की।

4.30 चूंकि इस बात के स्पष्ट संकेत थे कि यह पुनरुत्थान मजबूती प्राप्त कर रहा था, यह महसूस किया गया कि मुख्य नीतिगत साधन ऐसे स्तर पर थे जो संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था की बजाय संकट से तेजी से उबरती अर्थव्यवस्था के अधिक अनुरूप थे और इसलिए यह जरूरी था कि समायोजनकारी नीतिगत दृष्टिकोण से हटने की प्रक्रिया को जारी रखा जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए, 2010-11 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने पॉलिसी दरों में छः बार वृद्धि की जिससे एलएएफ के तहत रेपो दर में संचयी तौर पर 175 आधार बिन्दु (बीपीएस) की वृद्धि हुई और यह 6.5 प्रतिशत पर पहुंच गई तथा रिवर्स रेपो दर में 225 आधार बिन्दु की बढ़ोतरी करके उसे 5.5 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी प्रारक्षित अनुपात को बैंकों की निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 6 प्रतिशत पर बनाए रखा है। इस प्रकार 2010-11 में, भारतीय रिजर्व बैंक के अपेक्षित स्तर से लगातार ऊपर बनी रही उच्च मुद्रास्फीति के साथ विकास की रफ्तार ने इस बात को जरूरी कर दिया कि मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति और स्फीतिकारी संभावनाओं पर काबू पाने पर केंद्रित रहे।

4.31 भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की पहली त्रैमासिक समीक्षा (27 जुलाई 2010) में यह इंगित किया था कि अब प्रत्येक त्रैमासिक समीक्षा के बाद डेढ़ महीने के अंतराल पर मध्य-त्रैमासिक समीक्षा की जाए। ऐसा करते हुए, बैंक का उद्देश्य था कि इतर-चक्रिय कार्रवाइयों में से आकस्मिकता का तत्व हटा दिया जाए। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने 16 सितंबर 2010 और 16 दिसंबर 2010 को मध्य-त्रैमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा की घोषणा की।

4.32 2010-11 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थ-तंत्र में पर्याप्त नकदी बनाए रखने की नीति जारी रखी ताकि मूल्य और वित्तीय स्थिरता के उद्देश्य के अनुरूप उत्पादक प्रयोजनों के लिए ऋण

संबंधी सभी वैध ज़रूरतें पूरी की जा सकें। नकदी का प्रबंधन खुले बाज़ार प्रचालनों (ओएमओ), बाज़ार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस), एलएएफ और अनेक विशेष सुविधाओं का उपयुक्त उपयोग करके किया गया। हालांकि अर्थतंत्र में समग्र नकदी नीतिगत दृष्टिकोण के अनुरूप घाटे में ही रही है, मुख्यतः बड़े सरकारी नकद शेषों के बने रहने के चलते, मुद्रा की दुर्लभता का स्तर एनडीटीएल के (+) (-) 1 प्रतिशत के भारतीय रिज़र्व बैंक के अपेक्षित स्तर से अधिक बना रहा है। इसके अतिरिक्त, नकदी का घाटा ऐसे संरचनागत कारकों के कारण बढ़ा है जैसेकि प्रवृत्ति से कहीं अधिक मुद्रा विस्तार और बैंक जमाओं में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि जबकि 2010-11 में ऋण-वृद्धि में तेज़ी हुई। जहां नकदी के घाटे ने मौद्रिक नीति के संकेतों के सम्प्रेषण में सुधार किया जब अनेक बैंकों ने जमा एवं उधार की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, अत्यधिक घाटे निधियों की उपलब्धता और लागत में अनिश्चितता पैदा करते हैं जिससे ऋण सुपुर्दगी बनाए रखने में बैंकिंग प्रणाली को मुश्किल होती है।

4.33 नकदी दबावों के लगातार बने रहने को देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2010 में कुछ उपायों को कार्यान्वित किया जैसे कि एलएएफ के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उनके एनडीटीएल के 2.0 प्रतिशत तक की अतिरिक्त नकदी सहायता, दूसरी एलएएफ (एसएलएएफ) को जारी रखना और सरकारी प्रतिभूतियों की ओएमओ खरीद। तदनंतर, 16 दिसंबर 2010 के मध्य-त्रैमासिक समीक्षा में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 दिसंबर 2010 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एसएलआर को उनके एनडीटीएल के 25 प्रतिशत से घटाकर 24 प्रतिशत कर दिया। इसके अलावा, इसने अगले एक महीने में 48,000 करोड़ रुपये की कुल राशि की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद हेतु ओएमओ नीलामियां संचालित करने का निर्णय लिया। यह भी साफ तौर पर बता दिया गया कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था फैलेगी, इसे प्राथमिक नकदी की ज़रूरत होगी, जो मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप तरीके से मुहैया कराई जानी होगी। इस प्रकार नकदी का प्रावधान करने का अर्थ मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव नहीं समझ लेना चाहिए क्योंकि मुद्रास्फीति अभी भी मुख्य चिन्ता बनी हुई है।

4.34 सार में, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की बुनियादी रफ्तार बरकरार है। मुद्रास्फीति में थोड़ी कमी ज़रूर आई है लेकिन यह आरबीआई के अपेक्षित स्तर से काफी अधिक है। इसके अलावा, घरेलू मांग और उच्च वैश्विक वस्तु-मूल्यों की ओर से मुद्रास्फीति संबंधी जोखिम अधिक है। इसलिए, मांग-पक्ष के दबावों के बढ़ने के प्रति मुद्रास्फीति के मोर्चे पर निरंतर सजग रहने की ज़रूरत है। हाल के समय में आरबीआई के लिए नकदी प्रबंधन करना एक बड़ी चुनौती रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक का यह प्रयास है कि नकदी से जुड़े दबावों को इस तरह से कम करे जो मुद्रास्फीति पर काबू पाने और स्फीतिकारी संभावनाओं पर रोक लगाने के मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप हो।

¹ 19 नवंबर 2010 तक की अवधि के संबंध में।

4.35 मौद्रिक नीति का मौजूदा रुख जो बैंक की दूसरी त्रैमासिक समीक्षा (नवंबर 2010) में इंगित किया गया, इस प्रकार है:

- क. स्फीतिकारी दबावों में और वृद्धि के प्रति कार्रवाई करने के लिए तैयार रहते हुए मुद्रास्फीति पर काबू पाना और स्फीतिकारी संभावनाओं पर रोक लगाना।
- ख. मूल्य, उत्पादन और वित्तीय स्थिरता के अनुरूप ब्याज दर व्यवस्था बनाए रखना।
- ग. नकदी की सक्रिय प्रबंध-व्यवस्था करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह मूलतः संतुलित रहे, जिसमें न तो नकदी अधिशेष मौद्रिक प्रेषण को मंद करे और न ही नकदी घाटा निधियों के प्रवाह को अवरुद्ध करे।

इसी दस्तावेज़ में भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा कि 'मौजूदा विकास और मुद्रास्फीति के रूझानों के आधार पर ही, रिज़र्व बैंक का विश्वास है कि निकट भविष्य में दर संबंधी और कार्रवाइयां किए जाने की संभावना अपेक्षाकृत कम है'। विराम का यह संकेत इसे ज़रूरत पड़ने पर और अधिक नीतिगत कार्रवाई करने से नहीं रोकेगा और तदनुसार, आरबीआई ने इंगित किया कि "लेकिन, एक अनिश्चित विश्व में हमें ऐसे आघात पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है जो वैश्विक या घरेलू माहौल से पैदा हो सकते हैं। उस घोषित नीति और विशेषकर खाद्य मूल्यों में नए सिरे से उभरे स्फीतिकारी दबावों के अनुक्रम में, आरबीआई ने जनवरी 2010 में अपनी त्रैमासिक समीक्षा में पॉलिसी दरों में पुनः 25 आधार बिन्दु की वृद्धि की।

मौद्रिक समुच्चयों में व्याप्त रुख

4.36 वर्ष 2010-11 के दौरान, पिछले वर्ष के मुकाबले आरक्षित मुद्रा (एम₀) और संकीर्ण मुद्रा (एम₁)¹ की वृद्धि दरें अधिक रही हैं जबकि स्थूल मुद्रा (एम₃) की वृद्धि कम रही है (सारणी 4.10)। संकीर्ण और स्थूल मुद्रा की वृद्धि में आई कमी मुख्यतः मांग और मीयादी दो प्रकार की जमाराशियों में आई कमी के कारण है। (3 दिसंबर 2010 तक)।

आरक्षित मुद्रा (एम₀)

4.37 2010-11 के दौरान, वित्त वर्ष के आधार पर, एम₀ में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई (10 दिसंबर 2010 तक) जबकि पिछले वर्ष की तदनुसूचित अवधि में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (सारणी 4.11)।

4.38 इस अवधि में भारतीय रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी परिसंपत्तियों (एनएफए) में पिछले वर्ष की तदनुसूचित अवधि में हुई 1.5 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 11 दिसंबर 2010 की स्थिति के अनुसार वर्षानुवर्ष आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी परिसंपत्तियों में एक वर्ष पूर्व के 6.8 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 0.6 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई (चित्र 4.7)।

सारणी : 4.10: चुनिंदा मौद्रिक मानदंडों में घट-बढ़

(प्रतिशत)

मदें	वार्षिक घट-बढ़		3 दिस. 2010 की स्थिति के अनुसार वृद्धि दर			
	2008-09	2009-10	वित्त वर्ष के आधार पर		वर्षानुवर्ष के आधार पर	
			2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
एम ₀	6.4	17	1.7	6.3	15.3	22.2
एम ₁	9	18.6	5.1	3.1	18.3	16.5
एम ₃	19.3	16.8	9.6	8.2	18.6	15.3

स्रोत: आरबीआई

सारणी 4.11: आरक्षित मुद्रा में परिवर्तन के स्रोत

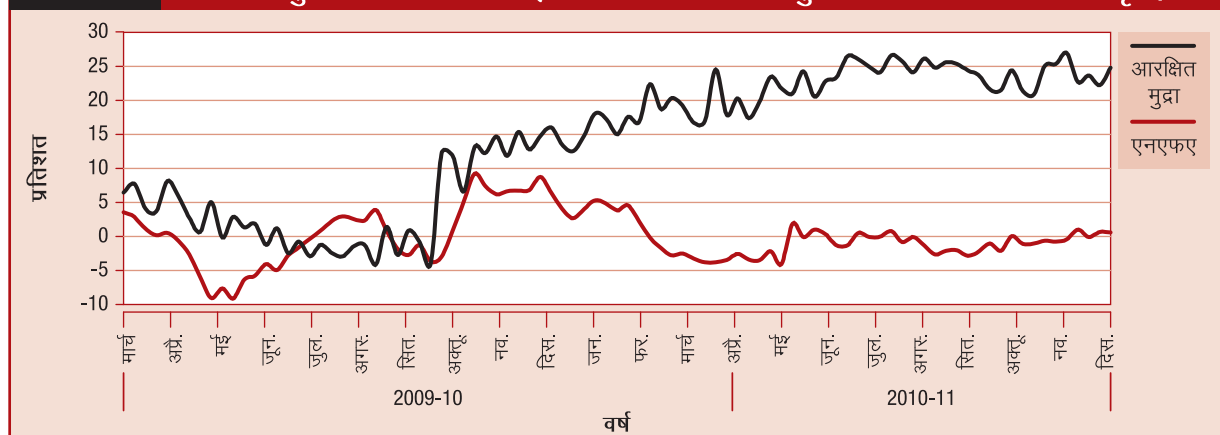
(प्रतिशत)

	वृद्धि दर				
	वित्त वर्ष पर आधारित		वर्षानुवर्ष		
	31, मार्च 2009 की तुलना में 2009-10	31, मार्च 2010 की तुलना में 10, दिस. 2010	12, दिस. 2008 की तुलना में 11, दिस. 2009	11, दिस. 2009 की तुलना में 10, दिस. 2010	
आरक्षित मुद्रा	17	1.6	8.4	12.8	24.8
क. घटक					
(क) संचलन में मुद्रा	15.7	10.8	14	17.2	19
(ख) भारि.बैं. में बैंकरों की जमाशियां	21	-19.6	-4.1	1.2	44.2
(ग) भारि.बैं. के पास 'अन्य' जमाशियां	-31.1	-34.4	0.3	-28	5.5
ख. आरक्षित मुद्रा के चुनिंदा स्रोत					
1. भारि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	-3.8	1.5	6.1	6.8	0.6
2. जनता के प्रति सरकार की मुद्रा संबंधी देनदारियां	12.1	7.7	4.4	10.6	8.6
3. भारि.बैं. की निवल गैर-मौद्रिक देनदारियां	-22.3	-1.5	17.1	19.5	-7.6

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

चित्र 4.7

आरक्षित मुद्रा और आर.बी.आई. की निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां—वार्षिक वृद्धि दर



4.39 इस वित्त वर्ष के दौरान (10 दिसंबर 2010 तक) अब तक केंद्र सरकार को मिलने वाले निवल आरबीआई ऋण में 70,856 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। ऐसा मुख्यतः एलएएफ के अंतर्गत रेपो प्रचालनों में बढ़ोतरी और बैंक की खुली बाजार खरीद के कारण हुआ जो केंद्र सरकार के नकद शेष में हुई वृद्धि से आंशिक रूप प्रतिसंतुलित हो गए। 10 दिसंबर 2010 की स्थिति के अनुसार, वर्षानुवर्ष आधार पर केंद्र सरकार को मिलने वाला निवल आरबीआई ऋण एक वर्ष पूर्व की 98,273 करोड़ रुपए की वृद्धि के मुकाबले 2,10,714 करोड़ रुपए रहा था।

संकीर्ण मुद्रा (एम₁)

4.40 संकीर्ण मुद्रा (एम₁) में 2008-09 के दौरान हुए 9.0 प्रतिशत के विस्तार के मुकाबले 2009-10 में 18.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2010-11 के दौरान, एम₁ की वृद्धि 2009-10 के मुकाबले सामान्यतया अधिक रही है, हालांकि नवीनतम पखवाड़े, जिसके संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं (अर्थात् 3 दिसंबर 2010) के दौरान इसमें काफी कमी आई। वित्त वर्ष के आधार पर एम₁ में चालू वर्ष के दौरान (3 दिसंबर 2010 तक) 3.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वर्षानुवर्ष आधार पर 3 दिसंबर 2010 की स्थिति के अनुसार एम₁ की वृद्धि एक वर्ष पूर्व के 18.3 प्रतिशत की तुलना में 16.5 प्रतिशत थी (चित्र 4.8)। चालू वित्त वर्ष के दौरान (3 दिसंबर 2010 तक), जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में 12.9 प्रतिशत (99,324 करोड़ रुपए) का विस्तार हुआ जबकि पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि में 9.8 प्रतिशत (64,962 करोड़ रुपये) की वृद्धि हुई थी।

4.41 एम₁ का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक नामशः बैंकों के पास मांग जमाराशियों में 3 दिसंबर 2010 तक की अवधि में 7.3 प्रतिशत की कमी आई जबकि पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि में 0.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई थी। वर्षानुवर्ष

आधार पर 3 दिसंबर 2010 को जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में वृद्धि एक वर्ष पहले के 17.2 प्रतिशत की तुलना में 18.7 प्रतिशत पर उच्च स्तर पर थी। इसी अवधि में, मांग जमाराशियों में हुई वृद्धि 13.7 प्रतिशत रही जबकि एक वर्ष पूर्व यह वृद्धि 19.9 प्रतिशत थी।

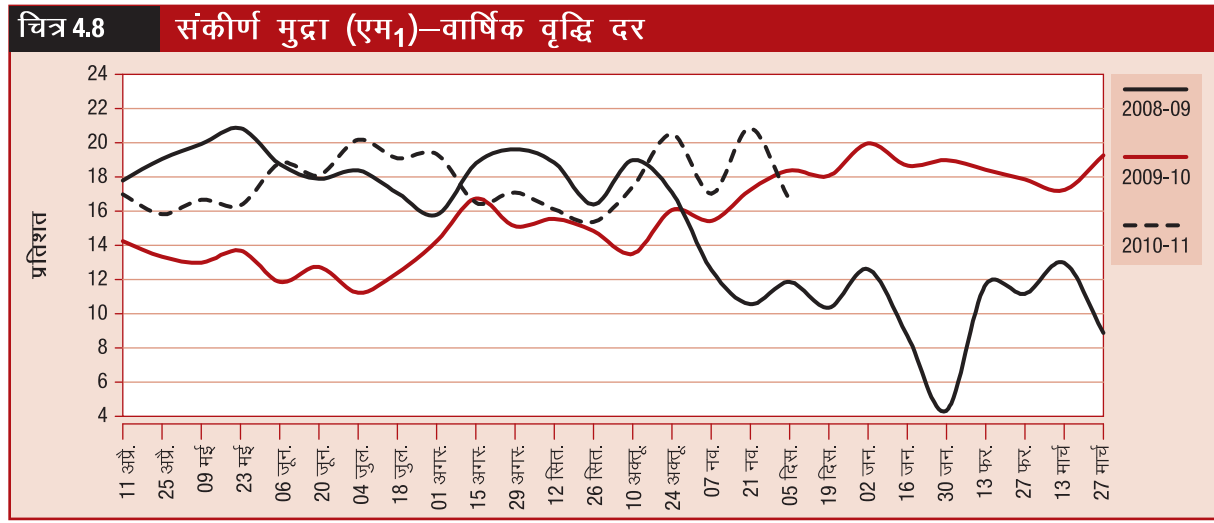
स्थूल मुद्रा (एम₃)

4.42 2009-10 के दौरान स्थूल मुद्रा (एम₃) की आपूर्ति में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 2009-10 के रिजर्व बैंक के वार्षिक नीति विवरण में परिकल्पित 17.0 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि से कम है।

4.43 स्थूल मुद्रा के मुख्य घटक और स्रोत सारणी 4.12 में दिए गए हैं।

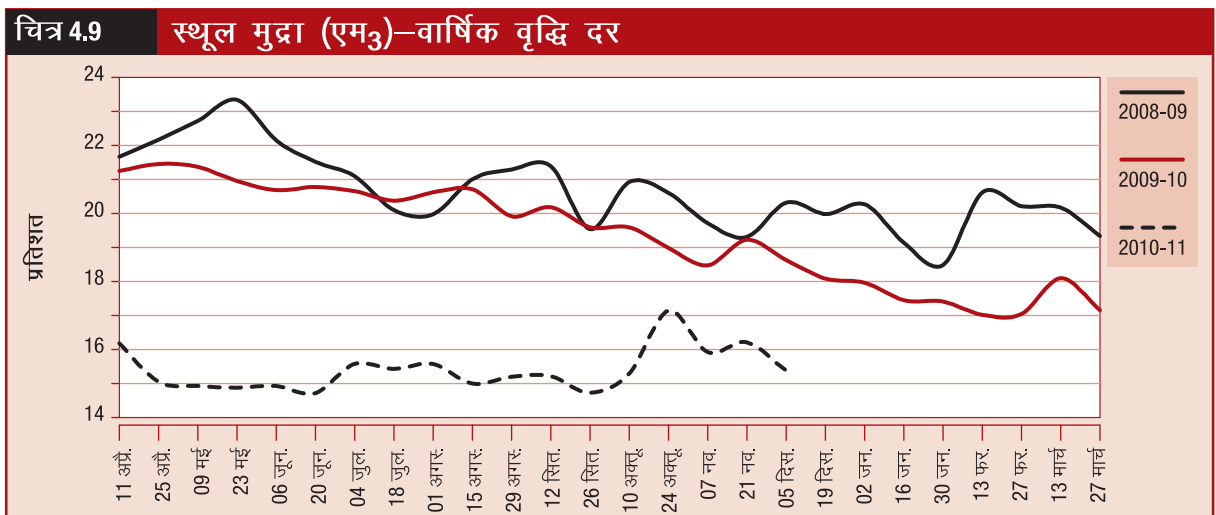
4.44 2010-11 के दौरान बैंक के पास मीयादी जमाराशियों में 10.1 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम दर पर वृद्धि हुई (3 दिसंबर 2010 तक) जबकि पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि के दौरान 11.2 प्रतिशत की दर पर वृद्धि हुई थी। वर्षानुवर्ष आधार पर 3 दिसंबर 2010 की स्थिति के अनुसार, मीयादी जमाराशियों में होने वाली वृद्धि एक वर्ष पूर्व के 18.7 प्रतिशत से कम होकर 14.9 प्रतिशत रह गई (सारणी 4.12)।

4.45 चालू वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान (3 दिसंबर 2010 तक) एम₃ में हुई वृद्धि 8.2 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि में यह 9.6 प्रतिशत रही थी। वर्षानुवर्ष आधार पर 3 दिसंबर 2010 की स्थिति के अनुसार एम₃ में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि में 18.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। (सारणी 4.12 और चित्र 4.9)। यह 2010-11 की वार्षिक नीति विवरण की दूसरी त्रैमासिक समीक्षा में निर्धारित 17.0 प्रतिशत के अनुमानित लक्ष्य से कम है।

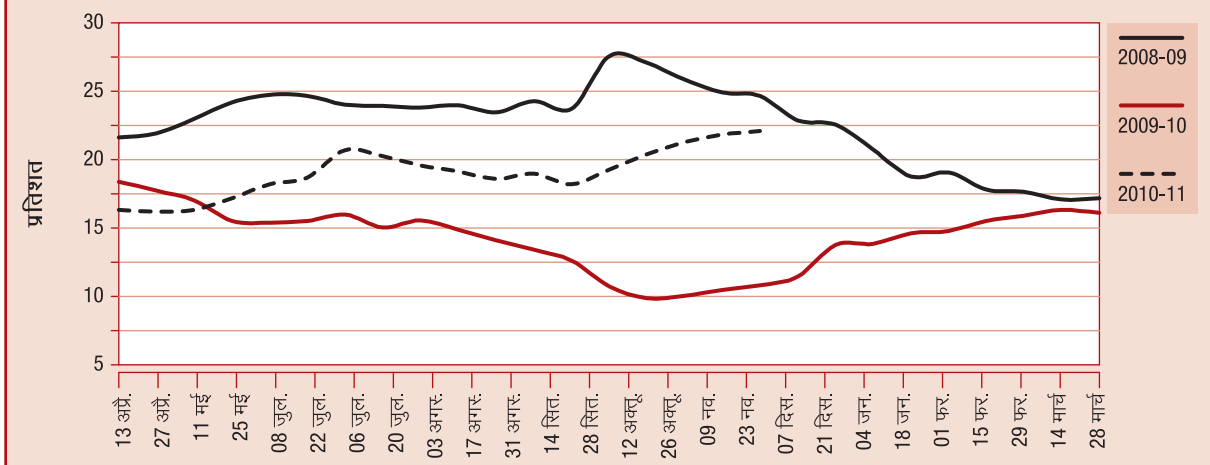


सारणी 4.12: मुद्रा भंडार (एम ₃) में परिवर्तन के स्रोत					
	वृद्धि दर				
	31 मार्च 2009 से 31 मार्च 2010	31 मार्च 2009 से 4 दिस. 2009	31 मार्च 2010 से 3 दिस. 2010	5 दिस. 2008 से 4 दिस. 2009	4 दिस. 2009 से 3 दिस. 2010
	(प्रतिशत)				
I. एम ₃ (संकीर्ण मुद्रा)	18.6	5.1	3.1	18.3	16.5
II. एम ₃ (स्थूल मुद्रा) (1+2+3+4)	16.8	9.6	8.2	18.6	15.3
1. जनता के पास उपलब्ध मुद्रा	15.4	9.8	12.9	17.2	18.7
2. बैंक के पास मांग जमाशियां	22.8	0.1	-7.3	19.9	13.7
3. बैंकों में सावधि जमाशियां	16.1	11.2	10.1	18.7	14.9
4. भा.रि.बैं. के पास "अन्य" जमाशियां	-31.1	-33.7	9.1	-23.1	13.4
II. मुद्रा भंडार (एम ₃) में परिवर्तन के स्रोत					
1. सरकार को प्राप्त निवल बैंक ऋण जिसमें से :	30.5	19.4	8.7	38.2	18.8
सरकार के अन्य बैंक ऋण	19.7	19.5	6.9	26.7	7.1
2. वाणिज्यिक क्षेत्र को प्राप्त बैंक ऋण जिसमें से :	15.9	4.8	10.3	10.5	21.9
वाणिज्यिक क्षेत्र के अन्य बैंक ऋण	16.3	5.1	10.3	10.4	22.0
3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	-5.2	-0.3	5.3	9.0	0.1
4. जनता के प्रति सरकार की मुद्रा संबंधी देनदारियां	12.1	7.7	4.4	10.6	8.6
5. बैंकिंग क्षेत्र की सावधि जमाशियों के अलावा निवल मुद्रा भिन्न देनदारियां	16.0	15.1	9.9	23.4	10.8
ज्ञापन मर्दें					
1. मुद्रा गुणक (एम ₃ /एम ₀)	4.85				
2. मुद्रा की गति	1.20				
3. निवल घरेलू परिसंपत्तियां	25.4	13.5	9.1	22.2	20.6
4. निवल घरेलू ऋण	20.2	9.2	9.8	18.2	20.9

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक



चित्र 4.10 वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए जाने वाला बैंक ऋण-वार्षिक वृद्धि दर



4.46 एम₃ के स्रोतों में, वाणिज्यिक क्षेत्र को मिलने वाले बैंक ऋण में नवंबर 2009 से बढ़ोतरी हो रही है (चित्र 4.10)।

मुद्रा गुणक

4.47 2009-10 के दौरान एम₀ में हुई अधिक विस्तार की दर एम₃ की तुलना में अधिक थी। तदनुसार एम₀के प्रति एम₃ के अनुपात (मुद्रा गुणक) में गिरावट देखी गई। मार्चान्त 2010 में यह अनुपात मार्चान्त 2009 के 4.11 की तुलना में 4.8 के स्तर पर मामूली सा कम था। चालू वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान स्थूल मुद्रा आपूर्ति की तुलना में आरक्षित मुद्रा के अधिक वृद्धि दर्ज करने के चलते मुद्रा गुणक में सामान्यतः गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। 3 दिसंबर 2010 की स्थिति के अनुसार मुद्रा गुणक पिछले वर्ष की इसी तारीख के 5.2 की तुलना में 4.9 था (चित्र 4.11)।

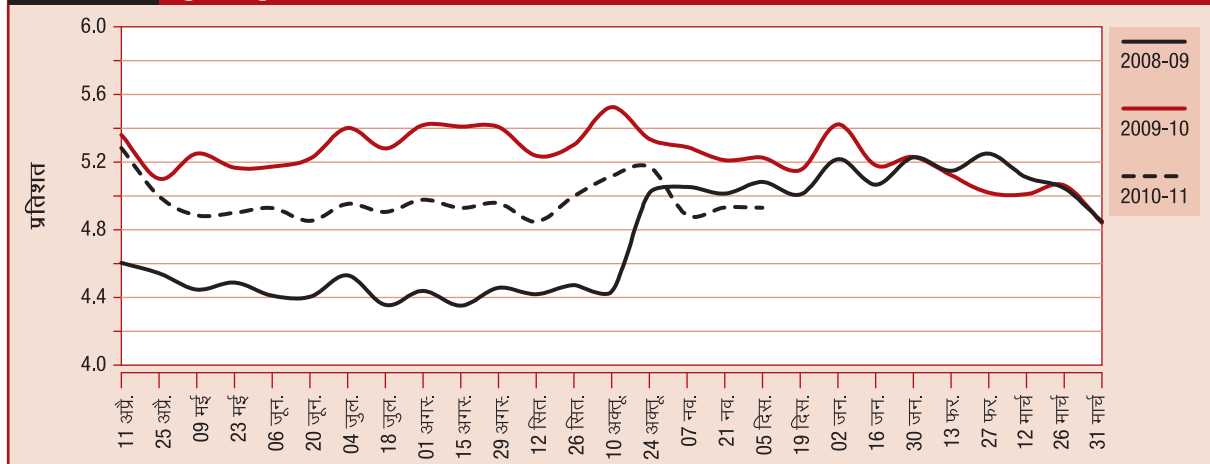
अन्य मौद्रिक संकेतकों में घट बढ़

4.48 जहां दिसंबर 2010 में वर्षानुवर्ष मुद्रा आपूर्ति (एम₃) वृद्धि 16.5 प्रतिशत के स्तर पर 17 प्रतिशत के सांकेतिक

अनुमान के निकट थी, 24.4 प्रतिशत के स्तर पर खाद्य-भिन्न ऋण वृद्धि 20 प्रतिशत के सांकेतिक अनुमान से कहीं अधिक थी। हाल की अवधि में ऋण विस्तार जमाराशियों में हुए विस्तार की अपेक्षा कुछ तेजी से हुआ है। जमाराशियों में समनुरूप वृद्धि हुए बिना तीव्र ऋण वृद्धि सम्पोषणीय नहीं होती क्योंकि केन्द्रीय बैंक को अधिक उधार लेने पर निर्भर होना पड़ता है। नवम्बर 2010 के आरंभ में ओएमओ नीलामियों के माध्यम से 67,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्राथमिक नकदी के अंतःक्षेपण के परिणामस्वरूप अर्थतंत्र में संरचनागत नकदी घाटे में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

4.49 स.घ.उ. में औसत एम₃ के अनुपात द्वारा यथामापित मौद्रिक गहनता 1990-91 के 43.8 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 83.1 प्रतिशत हो गई। इसका श्रेय देश में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार और वित्तीय क्षेत्र के विकास को दिया जा सकता है। सकल घरेलू उत्पाद में औसत एम₁ के अनुपात द्वारा यथामापित अर्थव्यवस्था के मुद्रीकरण ने इस अवधि के दौरान, भले ही धीमी दर पर, लेकिन वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई है। 1990-91 में यह

चित्र 4.11 मुद्रा गुणक में घट बढ़



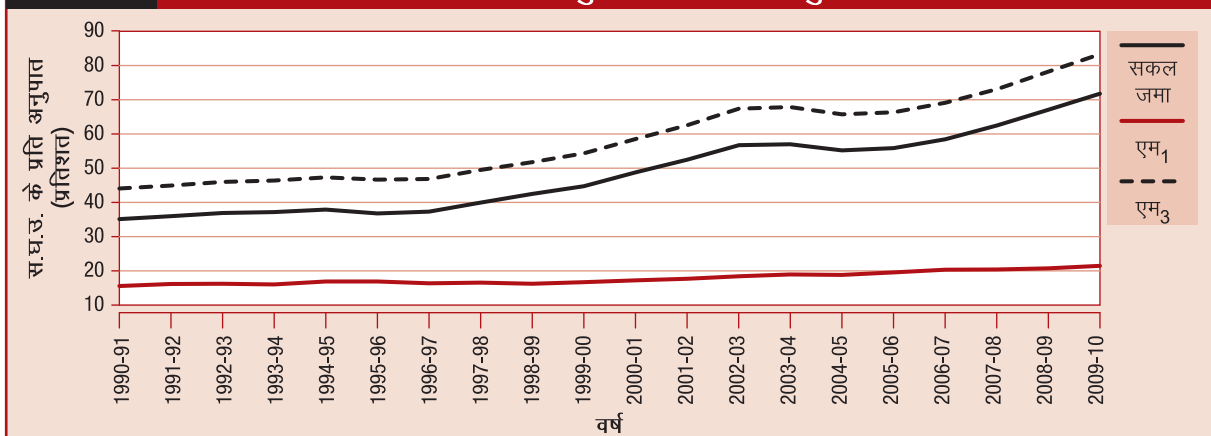
सारणी 4.13: चुनिंदा मौद्रिक समुच्चय (संघउ० के प्रति अनुपात)

	बाज़ार मूल्यों पर संघउ० के प्रतिशत के रूप में (आधार 1999-2000)					
	जनता के पास मुद्रा	बैंकों में मांग जमाराशियां	बैंकों में मीयादी जमाराशियां	सकल जमाराशियां	एम ₁	एम ₃
1990-91	8.7	6.4	28.5	34.9	15.3	43.8
1991-92	8.8	6.9	28.8	35.7	15.9	44.7
1992-93	8.6	6.9	29.8	36.6	16	45.7
1993-94	8.8	6.6	30.3	36.9	15.7	46.1
1994-95	9.1	7.2	30.4	37.6	16.7	47.1
1995-96	9.4	6.7	29.8	36.5	16.6	46.4
1996-97	9.2	6.5	30.5	37	16.1	46.6
1997-98	9.3	6.7	33	39.7	16.3	49.2
1998-99	9.1	6.7	35.5	42.2	16	51.5
1999-00	9.5	6.8	37.7	44.5	16.4	54.1
2000-01	9.6	7.2	41.3	48.5	17	58.2
2001-02	10	7.4	44.9	52.2	17.5	62.3
2002-03	10.5	7.5	49	56.5	18.2	67.1
2003-04	10.7	7.8	48.9	56.7	18.7	67.6
2004-05*	10.4	8	47	55	18.5	65.5
2005-06*	10.3	8.8	46.8	55.6	19.3	66.1
2006-07*	10.5	9.4	48.8	58.2	20	68.9
2007-08*	10.5	9.5	52.7	62.2	20.1	72.8
2008-09*	11	9.3	57.5	66.8	20.4	77.9
2009-10*	11.4	9.7	61.9	71.5	21.2	83.1

स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: *2004-05 के आधार के साथ स.घ.उ. आंकड़ों पर आधारित

चित्र 4.12 स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में चुनिंदा मौद्रिक-समुच्चय



अनुपात 15.3 प्रतिशत था और बढ़कर 2009-10 में यह 21.2 प्रतिशत तक पहुंच गया (सारणी 4.13 और चित्र 4.12)।

नकदी प्रबंधन

4.50 भारतीय रिजर्व बैंक ने खुले बाजार के प्रचालनों (ओएमओ), नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ), नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) के माध्यम से नकदी प्रबंधन की सक्रिय नीति जारी रखी। 2010-11 के दौरान अब तक आरबीआई में केन्द्र का नकद अधिशेष स्वायत्त नकदी का प्रमुख संचालन रहा है। संचलन में मुद्रा स्वायत्त नकदी का दूसरा प्रमुख निर्धारक रहा है। रिजर्व बैंक की एलएएफ विंडो जो लगभग 18 माह तक अधिशेष की स्थिति में रही थी, मई अंत 2010 तक घाटे की स्थिति में चली गई और बाद में यह प्रवृत्ति लगातार बनी रही।

4.51 2010-11 की पहली तिमाही में नकदी की स्थितियों में उल्लेखनीय परिवर्तन हो गया। फरवरी 2010 से अर्थात्तंत्र में अधिशेष नकदी की मात्रा में धीरे-धीरे आई कमी ने आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति के चरणबद्ध रूप से सामान्य होते जाने को

प्रतिबिम्बित किया। तदनुसार, एलएएफ अवशोषण की स्थिति में रही। हालांकि अवशोषण की मात्रा धीरे-धीरे कम हो गई। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए और स्फीतिकारी दबावों के और बढ़ने पर रोक लगाने के लिए आरबीआई ने अप्रैल 2010 में 2010-11 की वार्षिक मौद्रिक नीति में सीआरआर के साथ-साथ रेपो और रिवर्स रेपो दर प्रत्येक में 25 आधार बिन्दु की वृद्धि की। तत्पश्चात्, घरेलू बाजार में अधिशेष नकदी धीरे-धीरे कम हो गई। एक उल्लेखनीय घटना यह थी कि लगभग 18 माह तक अधिशेष स्थिति में रहने के बाद आरबीआई की एलएएफ विंडो मई 2010 के अंत में घाटे की दिशा में प्रवृत्त हो गई जो मुख्यतः 3जी (थर्ड जनरेशन स्पैक्ट्रम) और बीडब्ल्यूए (ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस) नीलामियों और परिणामतः आरबीआई में केन्द्र सरकार के नकदी शेष में नकदी के अन्तरण के कारण हुआ। नकदी में अस्थायी कमी को संभावना के चलते, आरबीआई ने ऐसे उपाय किए जिनसे एससीबी को अपने एनडीटीएल के 0.5 प्रतिशत तक एलएएफ के तहत अतिरिक्त नकदी सहायता के प्रयोग की अनुमति दी गई और 28 मई से 2 जुलाई 2010 की अवधि के

सारणी 4.14 : नकदी प्रबंधन (₹ करोड़)

निम्न माह के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया	एलएएफ	एमएसएस	केन्द्र का अधिशेष @	कुल
2009				
जनवरी	54,605	1,08,764	-9,166	1,54,203
फरवरी	59,820	1,01,991	-9,603	1,52,208
मार्च**	1,485	88,077	16,219	1,05,781
अप्रैल	1,08,430	70,216	-40,412	1,38,234
मई	1,10,685	39,890	-6,114	1,44,461
जून	1,31,505	22,890	12,837	1,67,232
जुलाई	1,39,690	21,063	26,440	1,87,193
अगस्त	1,53,795	18,773	45,127	2,17,695
सितम्बर	1,06,115	18,773	80,775	2,05,663
अक्टूबर	84,450	18,773	69,391	1,72,614
नवम्बर	94,070	18,773	58,460	1,71,303
दिसम्बर	19,785	18,773	1,03,438	1,41,996
2010				
जनवरी	88,290	7,737	54,111	1,50,138
फरवरी	47,430	7,737	33,834	89,001
मार्च*	990	2,737	18,182	21,909
अप्रैल	35,720	2,737	-28,868	9,589
मई	6,215	317	-7531	-999
जून	-74,795	317	76,431	1953
जुलाई	1,775	0	16,688	18,463
अगस्त	11,815	0	20,054	31,869
सितम्बर	-30,250	0	65,477	35,227
अक्टूबर	-1,17,660	0	86,459	-31,201
नवम्बर	-1,03,090	0	93,425	-9,665

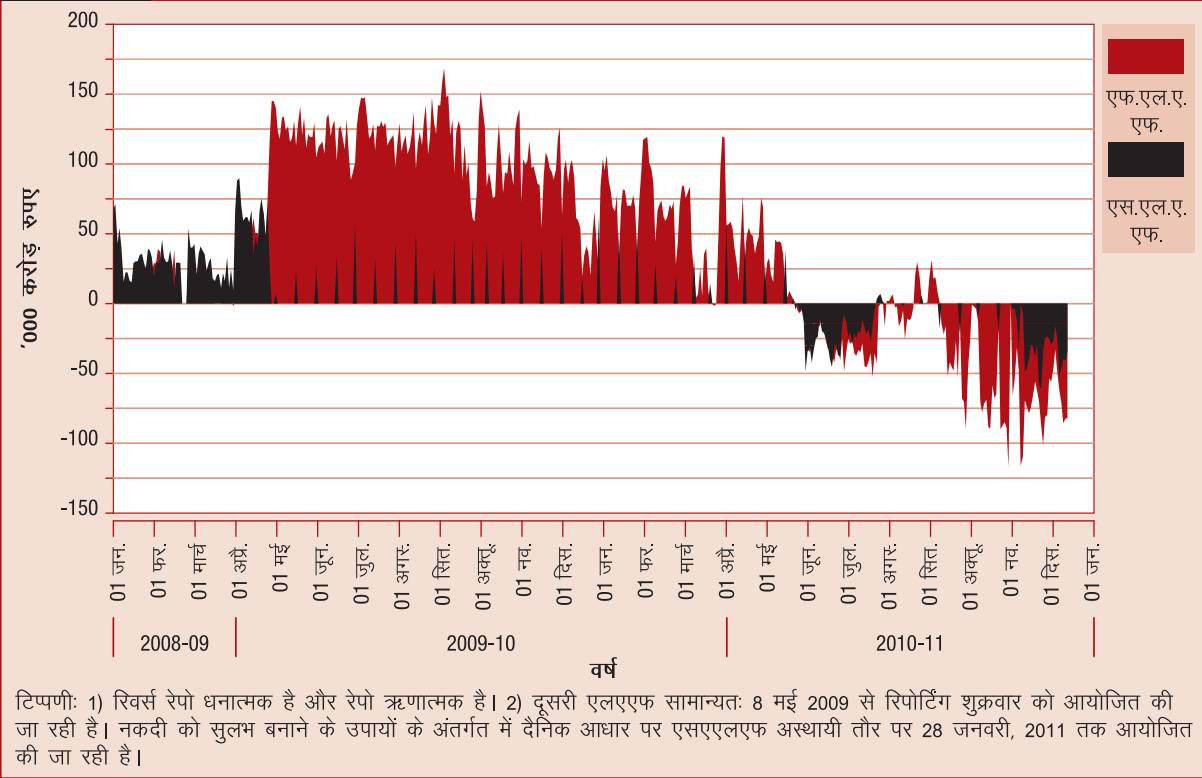
टिप्पणी: * अधिशेष के मामले में आरबीआई में न्यूनतम नकदी शेष को छोड़कर

** आंकड़े 31 मार्च तक हैं।

- एलएएफ के तहत ऋणात्मक चिह्न एलएएफ के तहत नकदी अंतःक्षेपण को दर्शाता है।

@ केन्द्र अधिशेष के तहत ऋणात्मक चिह्न डब्ल्यूएमए/ओडी (अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट) को दर्शाता है।

चित्र 4.13 एल.ए.एफ. – रिवर्स रेपो और रेपो की मात्रा



लिए दैनिक आधार पर एसएलएएफ की सुविधा दी गई। जून 2010 के दौरान एलएएफ के तहत औसत दैनिक नकदी अंतःक्षेपण मई 2010 में लगभग 33,000 करोड़ रुपए के औसत दैनिक अवशोषण के मुकाबले लगभग 47,000 करोड़ रुपए था। (सारणी 4.14 और चित्र 4.13)।

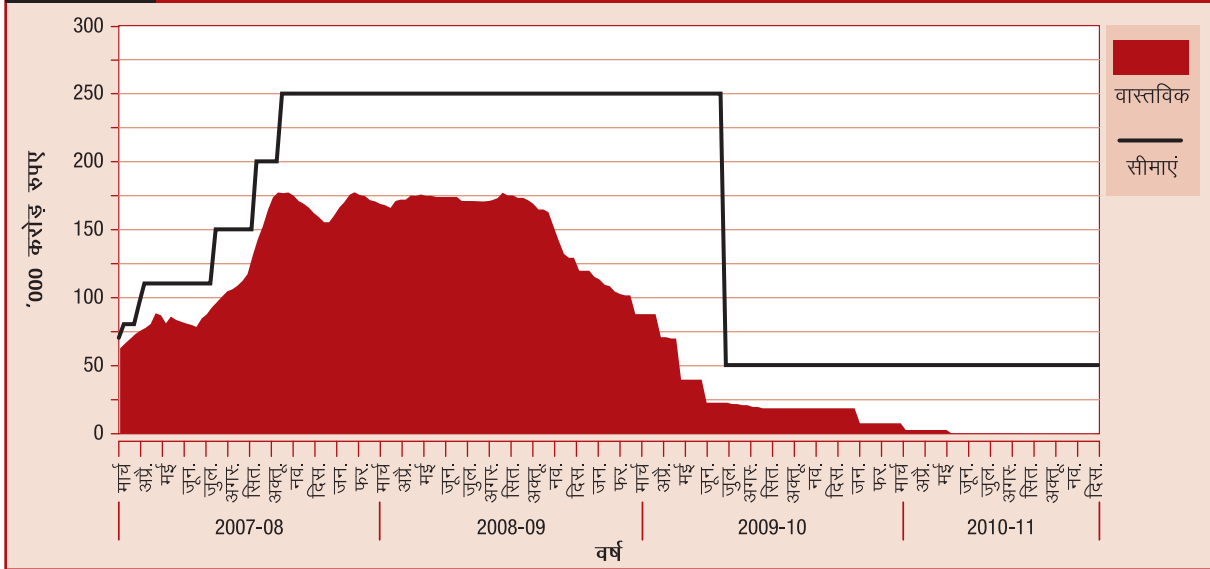
4.52 2010-11 में, दूसरी तिमाही जुलाई-सितम्बर के दौरान नकदी स्थितियां सामान्यतः घाटे की रहीं। 2 जुलाई 2010 को आरबीआई ने रेपो व रिवर्स रेपो दरों में प्रत्येक में 25 आधार बिन्दु की वृद्धि की जिससे वे क्रमशः 5.50 प्रतिशत और 4.0 प्रतिशत हो गईं। नकदी लगातार घाटे की स्थितियों में बने रहने के चलते, बैंक ने पूर्व में आरंभ की गई नकदी सुलभ बनाने के उपायों को जारी रखा। एससीबी को अपने एनडीटीएल² को 0.5 प्रतिशत तक एलएएफ के तहत अतिरिक्त नकदी सहायता का लाभ उठाने की अनुमति दी गई। दैनिक आधार पर एसएलएएफ को 16 जुलाई 2010 तक बढ़ा दिया गया। प्रचलित समग्र नकदी स्थितियों के मूल्यांकन के बाद और नकदी प्रबन्धन में एससीबी को लोचशीलता प्रदान करने के लिए, आरबीआई ने दैनिक आधार पर एसएलएएफ को 30 जुलाई 2010 तक और बढ़ा दिया। जुलाई 2010 के दौरान एलएएफ के तहत औसत दैनिक नकदी अंतःक्षेपण लगभग 47,000 करोड़ रुपए रहा। बदलते स्फीतिकारी माहौल को देखते हुए आरबीआई ने मौद्रिक नीति 2010-11 की पहली त्रैमासिक समीक्षा (27 जुलाई को घोषित) में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में क्रमशः 25 आधार बिन्दु और

50 आधार बिन्दु की वृद्धि कर इन्हें क्रमशः 5.75 प्रतिशत और 4.50 प्रतिशत कर दिया। अगस्त 2010 में नकदी की स्थितियों में सुधार हुआ (जो मुख्यतः 28 जुलाई 2010 को समयपूर्व बड़े सरकारी ऋण मोचन के कारण हुआ) और माह के दौरान नकदी का औसत दैनिक निवल अंतःक्षेपण गिरकर लगभग 1000 करोड़ रुपए के स्तर पर आ गया। अधिशेष नकदी (अगस्त अन्त से सितम्बर 2010 के आरंभ तक) की संक्षिप्त अवधि के बाद नकदी की स्थितियां फिर से अंतःक्षेपण की दिशा में चली गईं क्योंकि त्रैमासिक अग्रिम कर बहिर्वाहों के कारण नकदी आरबीआई के सरकारी खाते में अन्तरित हो गई थी। बृहत् आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर आरबीआई ने मध्य त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा (16 सितम्बर, 2010 को घोषित) में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में क्रमशः 25 आधार बिन्दु और 50 आधार बिन्दु की वृद्धि की। नकदी सितम्बर, 2010 के उत्तरार्ध में कम रही क्योंकि केन्द्र के नकदी अधिशेष में वृद्धि होनी शुरू हो गई थी और माह के दौरान औसत दैनिक निवल बकाया नकदी अंतःक्षेपण लगभग 24,000 करोड़ रुपए था।

4.53 सरकार के बकाया अधिशेष में बढ़ोतरी और त्र्यौहार के मौसम की मांग के कारण संचलन में मुद्रा में वृद्धि होने के कारण अक्टूबर, 2010 में फिर से नकदी में कमी आई। संपूर्ण अक्टूबर, 2010 में औसत दैनिक निवल बकाया नकदी अंतःक्षेपण लगभग 62,000 करोड़ रुपए था। तथापि, 29 अक्टूबर, 2010 को निवल नकदी अन्तःक्षेपण 100,000 करोड़ रुपए के आंकड़े

² यह सुविधा लेने के चलते एसएलआर बनाए रखने में होने वाली किसी कमी को पूरा करने के लिए बैंकों को दण्डित ब्याज की माफी लेने की अनुमति दी गई।

चित्र 4.14 बाजार स्थिरीकरण योजना



को पार कर गया। असमान नकदी दबाव को सहज बनाने के लिए आरबीआई ने कई अस्थायी उपायों की घोषणा की, नामशः 29 अक्टूबर और 1 नवम्बर, 2010 को विशेष एसएलएफ का आयोजन, 30 अक्टूबर, 2010 को एलएएफ के तहत विशेष दो दिवसीय रेपो नीलामी आयोजित की गई। एलएएफ के तहत अतिरिक्त नकदी सहायता का लाभ लेने के लिए एनडीटीएल के 1 प्रतिशत की सीमा तक एसएलआर बनाए रखने में आई कमी को पूरा करने के लिए दाण्डिक ब्याज माफ करना (30-31 अक्टूबर को)। आरबीआई ने बाद में नकदी सुलभ करने के इन उपायों को और बढ़ाया और 1-4 नवम्बर, 2010 के दौरान सभी दिवसों को एसएलएफ आयोजित की और एलएएफ के तहत अतिरिक्त नकदी सहायता का लाभ लेने के लिए एसएलआर बनाए रखने में कमी होने पर (एनडीटीएल के 1 प्रतिशत की सीमा तक) दाण्डिक ब्याज को माफ करने की छूट 7 नवम्बर, 2010 तक लागू की गई। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए और स्फीतिकारी संभावनाओं को काबू में रखने के लिए आरबीआई ने 2 नवम्बर, 2010 को मौद्रिक नीति की दूसरी त्रैमासिक समीक्षा में रेपो और रिवर्स रेपो दरों में 25 आधार बिन्दु तक की वृद्धि की। मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण के अनुरूप तथा नकदी की प्रचलित और उभरती स्थितियों के मूल्यांकन के आधार पर आरबीआई ने 4 नवम्बर, 2010 को अपने ओएमओ के तहत कुल 12000 करोड़ रुपए की कुल राशि की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद की और इस नीलामी से उसे कुल 8352 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। उच्च सरकारी शेष और संचलन में मुद्रा की बढ़ोत्तरी होने के चलते नवम्बर 2010 में नकदी में उच्च घाटे की स्थितियां जारी रहीं। 9 नवम्बर, 2010 को आरबीआई ने 16 दिसम्बर, 2010 तक प्रवृत्त रहने के लिए फिर से नकदी को सुलभ करने के उपाय किए (दैनिक आधार पर एसएलएफ,

एलएएफ के तहत नकदी सहायता का लाभ लेने के लिए एसएलआर बनाए रखने में कमी आने पर 1 प्रतिशत एनडीटीएल की सीमा तक दाण्डिक ब्याज माफ करना)। माह के दौरान औसत दैनिक निवल नकदी अंतःक्षेपण लगभग 99,300 करोड़ रुपए था। नकदी की स्थितियां दिसम्बर, 2010 (20 दिसम्बर तक) में अधिक घाटे में रही क्योंकि बड़े त्रैमासिक अग्रिम कर भुगतानों ने अर्थतंत्र में नकदी दबावों को बढ़ाया है। आरबीआई ने 9 दिसम्बर, और 15 दिसम्बर, 2010 को अपने ओएमओ के अंतर्गत नीलामी के जरिए कुल 12,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद की; और इन नीलामियों से उसे क्रमशः 10,120 करोड़ रुपए और 11,706 करोड़ रुपए की कुल राशि प्राप्त हुई। 1-20 दिसम्बर 2010 के दौरान औसत दैनिक निवल बकाया नकदी अंतःक्षेपण लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए था।

4.54 जहां अर्थतंत्र में समग्र नकदी, नीतिगत रूख के अनुरूप घाटे में रही है, कमी की यह सीमा आरबीआई के अपेक्षित स्तर से अधिक थी। आरबीआई ने (i) 18 दिसम्बर 2010 से एससीबी के एसएलआर को उनके एनडीटीएल के 25 प्रतिशत से घटाकर 24 प्रतिशत करने; (ii) अगले एक माह में 48,000 करोड़ रुपए की कुल राशि की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के लिए ओएमओ नीलामियां करवाने का निर्णय लिया। इन दोनों उपायों से सतत आधार पर 48,000 करोड़ रुपए की नकदी अंतःक्षेपित होने की संभावना है। एसएलआर में होने वाली कटौती प्रतिभूतियों को निर्मुक्त कर देगी और एक बार जब बैंक इन अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियों वाली एलएएफ विंडो के तहत उधार ले सकेंगे तो उधारकर्ता अधिक मंहगे स्रोतों की बजाय एलएएफ विंडो का विकल्प ले सकते हैं। (चित्र 4.14 और सारणी 4.15)।

सारणी 4.15 : मांग मुद्रा बाजार				
	मांग कारोबार (₹ करोड़)	मांग दर (प्रतिशत)^	एलएएफ (₹ करोड़)#	एमएसएम (₹ करोड़)*
2009-10				
मार्च 2009	23,818	4.17	33,360	88,077
अप्रैल 2009	21,820	3.28	1,01,561	75,146
मई 2009	19,037	3.17	1,25,728	45,955
जून 2009	17,921	3.21	1,23,400	27,140
जुलाई 2009	14,394	3.21	1,30,891	22,159
अगस्त 2009	15,137	3.22	1,28,275	19,804
सितम्बर 2009	16,118	3.31	1,21,083	18,773
अक्टूबर 2009	15,776	3.17	1,01,675	18,773
नवम्बर 2009	13,516	3.19	1,01,719	18,773
दिसम्बर 2009	13,302	3.24	68,522	18,773
जनवरी 2010	12,822	3.23	81,027	9,944
फरवरी 2010	13,618	3.17	78,661	7,737
2010-11				
मार्च 2010	17,624	3.51	37,640	3,987
अप्रैल 2010	16,374	3.49	57,150	2,737
मई 2010	16,786	3.83	32,798	922
जून 2010	14,258	5.16	-47,347	317
जुलाई 2010	18,954	5.54	-46,653	254
अगस्त 2010	15,916	5.17	-1048	0
सितम्बर 2010	17,212	5.50	-24,155	0
अक्टूबर 2010	17,840	6.39	-61,658	0
नवम्बर 2010	17,730	6.81	-99,311	0

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

^: दैनिक भारत मांग दर का औसत

* साप्ताहिक बकाया एमएसएम का औसत

एलएएफ के तहत औसत दैनिक अवशोषण

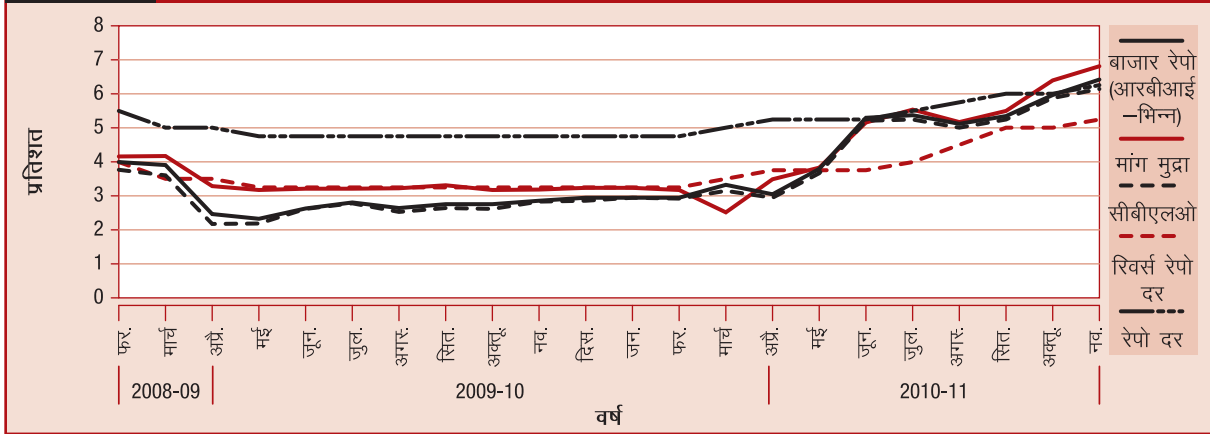
मुद्रा बाजार

4.55 मुद्रा बाजार 2010-11 के दौरान सामान्यतः सुव्यवस्थित बना रहा। वित्त वर्ष 2010-11 के आरंभ से मई 2010 तक मांग दर अधिकांशतः एलएएफ के अनौपचारिक दायरे की निम्नतर परिधि में बनी रही। मई अंत 2010 से नकदी के दुर्लभ हो जाने की स्थितियों जो 3 जी नीलामी/अग्रिम कर भुगतानों के चलते भारतीय रिजर्व बैंक स्थित केंद्र सरकार के खाते में नकदी जाने में प्रतिबिम्बित हुई, के कारण मांग दर बढ़ गई। पहली तिमाही के लिए औसत दैनिक मांग दर 4.16 प्रतिशत के स्तर पर थी। यह जुलाई 2010 तक एलएएफ के दायरे की ऊपरी परिधि में बनी रही क्योंकि केंद्र सरकार के अधिक नकदी शेष के कारण नकदी में घाटे की स्थितियां बनी रहीं। नकदी की स्थितियों में आए बदलाव के कारण मांग दर अगस्त के अंत और सितम्बर के शुरुआत में कम हुई। तथापि यह सितम्बर-मध्य 2010 से फिर बढ़ गई और इसने महीने के उत्तरार्ध में एलएएफ के अनौपचारिक

दायरे की ऊपरी परिधि को पार कर लिया था जो अधिक घाटे की नकदी की स्थितियों की शुरुआत को प्रतिबिम्बित करती है। औसत मांग दर बढ़कर दूसरी तिमाही में 5.40 प्रतिशत हो गई (सारणी 4.15)। मांग दर 2010-11 की तीसरी तिमाही में अब तक अधिकांशतः दायरे की ऊपरी परिधि से अधिक बनी हुई है जो अर्थतंत्र में बढ़ते नकदी के भार को प्रतिबिम्बित करता है। औसत मांग दर 2010-11 की तीसरी तिमाही (20 दिसम्बर 2010 तक) में 6.59 प्रतिशत थी। (चित्र 4.15)।

4.56 संपार्श्विक खण्डों की दरें 2010-11 के दौरान अब तक मांग दर के साथ-साथ घटती बढ़ती रही है बल्कि इससे कुछ कम रही है। मुद्रा बाजार के संपार्श्विकृत खण्ड में भारत औसत व्याज दर 2010-11 की पहली तिमाही के 3.97 प्रतिशत से बढ़कर दूसरी तिमाही में 5.20 प्रतिशत हो गई। संपार्श्विकृत उधार और ऋण बाध्यता (सीबीएलओ) और बाजार रेपो खण्ड में कारोबार की मात्रा इस अवधि के दौरान अधिक बनी रही जो

चित्र 4.15 मुद्रा बाजार दरों की घट-बढ़



बाजार की सक्रिय स्थितियां प्रतिबिम्बित करती है। बैंक संपार्श्विकृत खण्ड में निरन्तर प्रमुख उधारकर्ता समूह बने हुए हैं जबकि इन्हीं खण्डों में म्यूचुअल फंड निधियों के उधारदाता का मुख्य समूह बने हुए हैं। मुद्रा बाजार के संपार्श्विक खण्ड का निरन्तर प्रभुत्व बना हुआ है जिसका कारोबार इस वर्ष के दौरान अब तक कुल मात्रा के 80 प्रतिशत से अधिक हिस्से का रहा है।

जमा प्रमाणपत्र (सीडी)

4.57 हालांकि सीडी का औसत सकल निर्गमन 2010-11 के दौरान अब तक अधिक रहा था, सीडी की बकाया राशि में गिरावट हुई जो निवल निर्गमन में आई गिरावट को दर्शाती है। एससीबी द्वारा निर्गमित की गई सीडी की बकाया राशि में मामूली गिरावट आयी और यह मार्च 2010 के अंत में 3,41,054 करोड़ रुपये से कम होकर नवम्बर अंत 2010 में 3,32,982 करोड़ रुपये रह गई। यह बकाया राशि काफी अधिक अंतर-बैंक घट-बढ़ के साथ सीडी निर्गमित करने वाले बैंकों के कुल जमाओं का 7.45 प्रतिशत (19 नवम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार) थी। अप्रैल-नवम्बर 2010 के दौरान औसत निर्गमन लगभग 22,000 करोड़ रुपये राशि का था जबकि यह पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान 11,000 करोड़ रुपये के आसपास था। कुल सीडी निर्गमन के संबंध में प्रभावी ब्याज दर मार्चान्त 2010 में 6.07 प्रतिशत से बढ़कर 19 नवम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार 8.16 प्रतिशत हो गई।

वाणिज्यिक पत्र (सीपी)

4.58 वर्ष 2010-11 के दौरान अब तक वाणिज्यिक पत्र (सीपी) के बाजार में भी तेजी आयी है और पाक्षिक निर्गमन की संख्या भी बढ़ गई है। कारपोरेट द्वारा निर्गमित सीपी की बकाया राशि में भी वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है और यह मार्चान्त 2010 में 75,506 करोड़ रुपये से सितम्बर-अंत 2010 में 1,12,003 करोड़

रुपये और नवम्बर-अंत 2010 में 1,17,793 करोड़ रुपये हो गई। कुल सीपी निर्गमनों की भारत औसत बट्टा दर (डब्ल्यूएडीआर) मार्चान्त 2010 में 6.29 प्रतिशत से बढ़कर सितम्बर-अंत 2010 में 7.82 प्रतिशत हो गई और नवम्बर-अंत 2010 में 12.22 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई। कुल बकाया सीपी में 'पट्टादायी और वित्त कंपनियों', 'विनिर्माण कंपनियों', और 'अन्य वित्तीय संस्थाओं' का हिस्सा नवम्बर-अंत 2010 में क्रमशः लगभग 50 प्रतिशत, 39 प्रतिशत और 11 प्रतिशत था (सारणी 4.16)।

राजकोषीय हुंडियां (टी-बिल)

4.59 वर्ष 2010-11 के दौरान राजकोषीय हुंडियों का निर्गमन सरकार की नकद प्रबंधन की जरूरतों के साथ-साथ उभरती बाजार स्थितियों के अनुसार किया गया था। राजकोषीय हुंडियों की प्रतिस्पर्धी नीलामियों के लिए अधिसूचित राशियां वित्त वर्ष की पहली दो तिमाहियों के दौरान घटा दी गई थीं। गैर-प्रतिस्पर्धी आवंटन में वृद्धि का आकलन करने के पश्चात् राजकोषीय हुंडियों का बकाया स्टॉक 31 मार्च 2010 को 1,34,500 करोड़ रुपये से कम होकर 31 दिसम्बर 2010 को 1,26,269 करोड़ रुपये रह गया। विभिन्न अवधियों (91 दिवसीय, 182 दिवसीय) और 364 दिवसीय) की राजकोषीय हुंडियों की प्राथमिक बाजार आय इस वर्ष के दौरान मुख्यतः नकदी की स्थितियों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई मौद्रिक नीति की कार्रवाई के प्रभाव से बढ़ गई। 2009-10 की तुलना में 2010-11 के दौरान आय की प्रवृत्ति चित्र 4.16, 4.17 और 4.18 में दर्शाई गई है।

नकद का प्रबंधन

4.60 इस वर्ष के दौरान मई 2010 में नकद प्रबंधन बिल (सीएमबी) नामक एक नई अल्पावधिक लिखत की शुरुआत की गई थी। सीएमबी गैर-मानक, बट्टागत लिखतें हैं जो सरकार के अस्थायी नकद प्रवाह के अंतर को पूरा करने के लिए

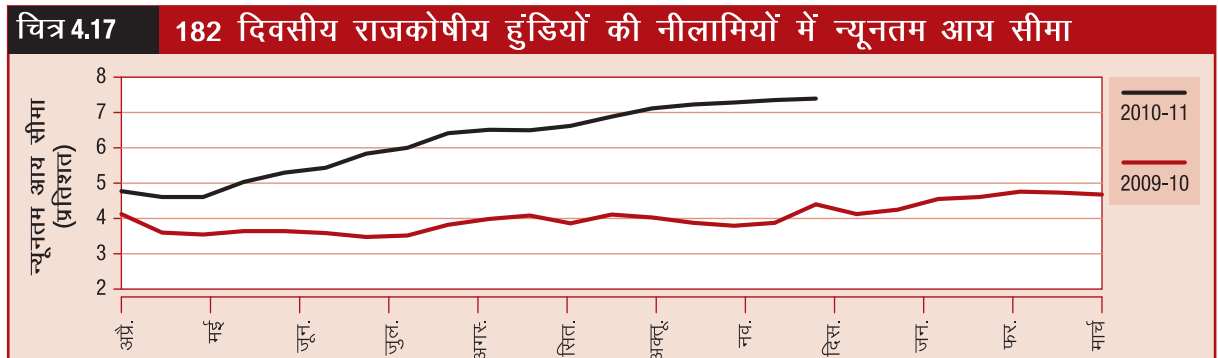
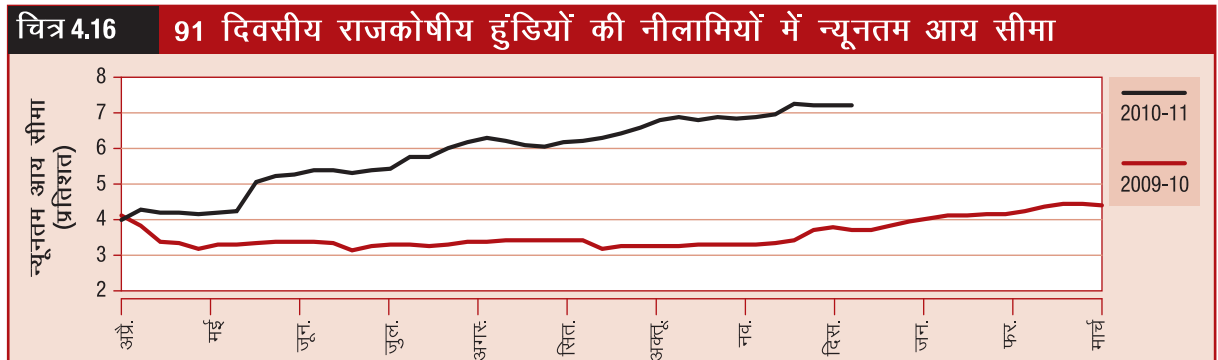
सारणी 4.16 : मुद्रा बाजार क्षेत्रों में कार्यकलाप

(₹ करोड़)

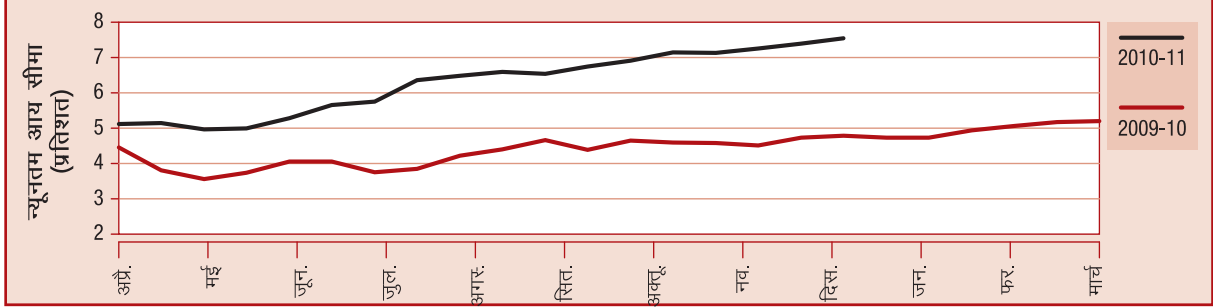
वर्ष/महीना	औसत दैनिक मात्रा (एक चरण)					वाणिज्यिक पत्र		जमा प्रमाण पत्र		
	मांग	बाजार रेपो	सीबीएलओ	जोड़	मुद्रा बाजार दर ^ (प्रतिशत)	सावधि धनराशि	बकाया	डब्ल्यूएडीआर (प्रतिशत)	बकाया	डब्ल्यूएडीआर (प्रतिशत)
अप्रैल 2009	10910	20545	43958	75413	2.41	332	52881	6.29	210954	6.48
मई 2009	9518	22449	48505	80472	2.34	338	60740	5.75	218437	6.2
जून 2009	8960	21694	53553	84207	2.69	335	68721	5	221491	4.9
जुलाई 2009	7197	20254	46501	73952	2.83	389	79582	4.71	240395	4.96
अगस्त 2009	7569	23305	57099	87973	2.62	461	83026	5.05	232522	4.91
सितम्बर 2009	8059	27978	62388	98425	2.73	381	79228	5.04	216691	5.3
अक्तूबर 2009	7888	23444	58313	89645	2.70	225	98835	5.06	227227	4.70
नवम्बर 2009	6758	22529	54875	84162	2.87	191	103915	5.17	245101	4.86
दिसम्बर 2009	6651	20500	55338	82489	2.91	289	90305	5.40	248440	4.92
जनवरी 2010	6411	14565	50571	71547	2.97	404	91564	4.80	282284	5.65
फरवरी 2010	6809	19821	63645	90275	2.95	151	97000	4.99	309390	6.15
मार्च 2010	8812	19150	60006	87968	3.22	393	75506	6.29	341054	6.07
अप्रैल 2010	8187	20319	50891	79397	3.03	345	98769	5.37	336807	5.56
मई 2010	8393	17610	42274	68277	3.72	338	109039	6.85	340343	5.17
जून 2010	7129	9481	31113	47723	5.22	447	99792	6.82	321589	6.37
जुलाई 2010	9477	12011	29102	50590	5.33	385	112704	6.93	324810	6.69
अगस्त 2010	7958	15553	45181	68692	5.05	281	126549	7.32	341616	7.17
सितम्बर 2010	8606	15927	53223	77756	5.29	617	112003	7.82	337322	7.34
अक्तूबर 2010	8920	14401	43831	67152	5.96	712	149620	12.15	343353	7.67
नवम्बर 2010	8865	9967	32961	51793	6.31	415	117793	12.22	332982	8.16

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणी: ^ दैनिक भारत मांग दर का औसत



चित्र 4.18 364 दिवसीय राजकोषीय हंडियों की नीलामियों में न्यूनतम आय सीमा



91 दिवस से कम की परिपक्वता के लिए जारी की जाती हैं। 2010-11 के दौरान मई 2010 में 12,000 करोड़ रुपए की कुल राशि के सीएमबी दो बार जारी किए गए, जिनकी परिपक्वता क्रमशः पांच और चार सप्ताहों की थी।

केन्द्र सरकार के उधार

4.61 2010-11 के केन्द्रीय बजट में केन्द्र सरकार के निवल बाजार उधार (दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से) की जरूरत पिछले वर्ष के दौरान जुटाए गए 3,97,957 करोड़ रुपए के मुकाबले 3,45,010 करोड़ रुपए आंकी गई थी। 1,12,133 करोड़ रुपए की अदायगियों सहित सकल बाजार उधारों का अनुमान 4,57,143 करोड़ रुपए लगाया गया था (पिछले वर्ष जुटाए गए 4,51,000 करोड़ रुपए की तुलना में जिनमें 33,000 करोड़ रुपये का एमएसएस अपरिबद्धकरण शामिल है)। चालू वर्ष के पूर्वार्ध के दौरान वास्तविक निर्गमन 2,84,000 करोड़ रुपए था (पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 28,000 करोड़ रुपये के एमएसएस अपरिबद्धकरण को छोड़कर 2,95,000 करोड़ रुपये के निर्गमन की तुलना में)। 23 सितम्बर, 2010 को जारी किए गए दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गमन कैलेंडर में इस वर्ष के उत्तरार्ध के दौरान 1,63,000 करोड़ रुपये जुटाने का प्रस्ताव है, जो बजट अनुमान में 10,000 करोड़ रुपये की कमी दर्शाता है।

4.62 वर्ष 2010-11 में सकल उधार की जरूरत पिछले वर्ष की जरूरत जैसी ही अधिक है। तथापि, बाजार उधार

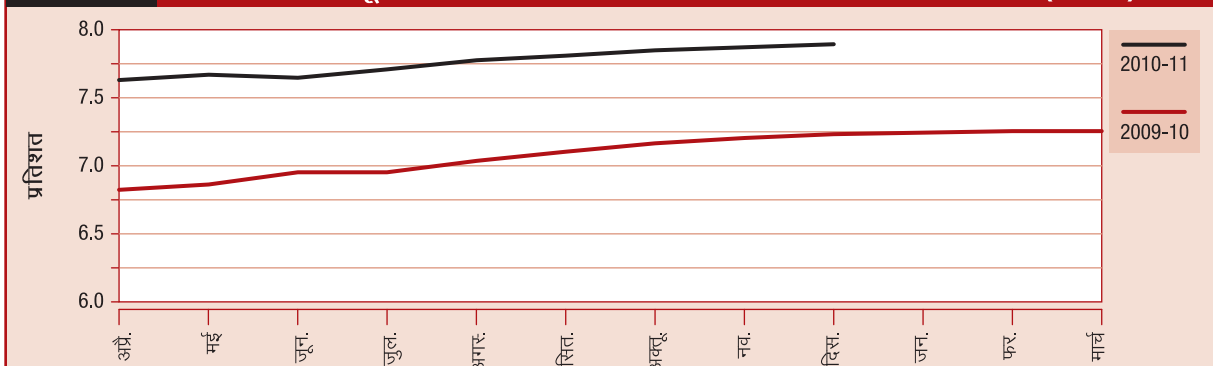
कार्यक्रम को सहजता से और किसी व्यवधान के बिना चलाया जाता है। इस वर्ष के दौरान सरकार ने पुनःखरीद प्रचालन किया है जिसमें 11,767 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों की वापस खरीद की गई।

4.63 2010-11 के दौरान (31 दिसम्बर 2010 तक) केन्द्र सरकार द्वारा दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से जुटाया गया सकल बाजार उधार पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि के दौरान जुटाए गए 3,83,000 करोड़ रुपये (एमएसएस के तहत किए गए निर्गमनों को छोड़कर) (निवल 3,46,911 करोड़ रुपये) के मुकाबले 3,84,000 करोड़ रुपये (निवल 2,98,342 करोड़ रुपये) था। इस वर्ष के दौरान (31 दिसम्बर, 2010 तक) जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत परिपक्वता पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि के दौरान के निर्गमनों के लिए 11.15 वर्षों की तुलना में थोड़ी अधिक 11.54 वर्ष थी। 2010-11 (31 दिसम्बर, 2010 तक) के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत आय बढ़कर 7.87 प्रतिशत हो गई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 7.21 प्रतिशत थी। (चित्र 4.19)।

10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय

4.64 सरकारी प्रतिभूतियों पर द्वितीयक बाजार की आय इस वर्ष व्यापक दायरे में बनी रही। सरकारी प्रतिभूतियों पर होने वाली आय को प्रभावित करने वालों में मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति संबंधी चिंताएं और आपूर्ति के मुद्दे प्रमुख कारक थे।

चित्र 4.19 दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमनों की भारित औसत आय (संचयी)



4.65 सरकारी प्रतिभूतियों की आय में अंतर-वर्षीय घट-बढ़ के लिए विभिन्न कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अप्रैल 2010 में हुई बढ़त मुख्यतः बाजार उधार कार्यक्रम की फ्रंट लोडिंग के फलस्वरूप पैदा हुए आपूर्ति के दबाव के कारण थी।

4.66 मई में, 3जी और बीडब्ल्यूए लाइसेंसों से बजटीय प्रावधान से अधिक संग्रहणों के प्राप्त होने के कारण उच्च राजकोषीय घाटे संबंधी चिंताएं कम हुई थीं। इन बेहतर संवेगों ने मई में आय को कम कर दिया। हालांकि बेहतर संवेगों का प्रभाव उच्च मुद्रास्फीति की चिंताओं और भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा को दुर्लभ बनाने की नीति से प्रतिसंतुलित हुआ था। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में दुर्लभ नकदी की स्थितियां आय पर उर्ध्वगामी दबाव डालने वाला एक प्रमुख कारक बनी रहीं। 10 वर्षीय आय जो 31 मार्च 2010 में 7.87 प्रतिशत थी, बढ़कर 31 दिसंबर 2010 को 7.94 प्रतिशत हो गई।

राज्य सरकार के उधार

4.67 बाईस राज्य सरकारों ने सकल आधार पर दिसम्बर अंत 2010 तक कुल 74,104 करोड़ रुपये की राशि जुटाई थी जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 25 राज्य सरकारों द्वारा 1,00,085 करोड़ रुपये जुटाए गए थे। न्यूनतम आय पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि के दौरान के 7.04 और 8.49 प्रतिशत की तुलना में 8.05 और 8.58 प्रतिशत के बीच घटती-बढ़ती रही है। भारत औसत आय 2009-10 की तदनु रूप अवधि के दौरान 8.02 प्रतिशत के मुकाबले दिसम्बर अंत 2010 तक 8.36 प्रतिशत और समग्र वर्ष के लिए 8.11 प्रतिशत पर आकलित की गई है। दिसम्बर, 2010 तक राज्य विकास ऋण (एसडीएल) पर प्राप्त आय और भारत सरकार की बेंचमार्क 10 वर्षीय प्रतिभूतियों के बीच अंतर 32-69 आधार बिन्दु पर अपेक्षाकृत कम था जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह अंतर 45-129 आधार बिन्दु था। आशा है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम हेतु अपनाई गई नपी-तुली कार्य नीतियां इसका अबाधित तरीके से पूरा होना सुनिश्चित करेंगी।

2010-11 के दौरान मौद्रिक नीति का रूख

4.68 समायोजनकारी मौद्रिक नीति जिसे सितम्बर-मध्य 2008 से चलाया गया था, ने बाजार के भागीदारों में विश्वास पैदा किया, अर्थव्यवस्था पर वैश्विक वित्तीय संकट के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया और यह सुनिश्चित किया कि हमारी अर्थव्यवस्था अन्य अर्थव्यवस्थाओं से पहले पुनरुत्थान शुरू करे। तथापि, बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति और स्फीतिकारी संभावनाओं पर इसके प्रभाव के जोखिम को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2009 में ही विस्तारकारी मौद्रिक नीति से हटने के प्रथम चरण की शुरुआत की। अप्रैल 2010 तक उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि

यह पुनरुत्थान ठोस था, हालांकि स्फीतिकारी दबाव बढ़ गए थे। तदनुसार, रेपो और रिवर्स रेपो दोनों दरों के साथ-साथ सीआरआर में 25 आधार बिन्दु की वृद्धि की गई थी। अप्रैल 2010 में मौद्रिक नीति दृष्टिकोण निम्नलिखित तीन विचारों से प्रेरित था। पहला, ऐसे माहौल जिसमें वास्तविक पॉलिसी दरें अभी तक ऋणात्मक बनी हुई थीं, में नीतिगत लिखतों को सामान्य करने की दिशा में एक नपे-तुले तरीके से आगे बढ़ने की आवश्यकता। दूसरा, यह सुनिश्चित करने की जरूरत कि मांग पक्ष की मुद्रास्फीति जड़ें न जमा ले। तीसरा, यह सुनिश्चित करते हुए कि सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को ऋण उपलब्ध हो, नकदी अवशोषित करने की मौद्रिक नीति को संतुलित किए जाने की जरूरत। अप्रैल 2010 में मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद उल्लेखनीय घटनाक्रम हुआ है। हालांकि पुनरुत्थान मजबूती पकड़ रहा था, मुद्रास्फीति के मोर्चे के घटनाक्रम ने कई चिंताएं उभारीं। 25 जून, 2010 को ईंधन की प्रशासित कीमतों में की गई वृद्धि से भी आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति के प्रभावित होने की संभावना थी। तदनुसार, एलएएफ के तहत रेपो और रिवर्स रेपो दोनों की दरों में 2 जुलाई 2010 को 25 आधार बिन्दु की बढ़ोत्तरी की गई थी। और अधिक व्यापक घरेलू पुनरुत्थान के तथा सुदृढीकरण के हित में एवं उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के दो अंकों के तत्कालीन स्तर के चलते भारतीय रिजर्व बैंक की पहली त्रैमासिक समीक्षा (जुलाई, 2010) में वास्तविक स.घ.उ. वृद्धि के आधारभूत अनुमान में ऊर्ध्वगामी संशोधन करके इसे इस वर्ष हेतु 8.5 प्रतिशत पर रखा गया तथा

सारणी 4.17 : पालिसी दरों में संशोधन

(प्रतिशत)

प्रभावी तिथि	रेपो दर	रिवर्स रेपो दर	सीआरआर
2009			
05.01.2009	5.50	4.00	
17.01.2009			5.00
05.03.2009	5.00	3.50	
21.04.2009	4.75	3.25	
2010			
13.02.2010			5.50
27.02.2010			5.75
19.03.2010	5.00	3.50	
20.04.2010	5.25	3.75	
24.04.2010			6.00
02.07.2010	5.50	4.00	
27.07.2010	5.75	4.50	
16.09.2010	6.00	5.00	
02.11.2010	6.25	5.25	
25.01.2011	6.50	5.50	

मार्च 2011 में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को बढ़ाकर 6.0 प्रतिशत रखा गया (सारणी 4.18)। इस निर्धारण के अनुरूप रेपो दर में 25 आधार बिन्दु और रिवर्स रेपो में 50 आधार बिन्दु की बढ़ोत्तरी की गई थी। मौद्रिक नीति की इन कार्रवाइयों का लक्ष्य था— मांग के दबावों और स्फीतिकारी संभावनाओं पर अंकुश लगाकर मुद्रास्फीति को कम करना, सतत् विकास के लिए प्रेरक वित्तीय स्थितियां बनाए रखना, नीतिगत कार्रवाइयों के अधिक कारगर प्रेषण के अनुरूप नकदी की स्थितियां सृजित करना और अल्पावधिक दरों की अस्थिरता कम करके उसे अपेक्षाकृत संकरे दायरे में लाना। नकदी का बदलती गति, विशेषकर अधिशेष और घाटे की स्थिति के बीच इस संदर्भ को देखते हुए, एलएएफ सहित भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की प्रचालन प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए एक कार्यदल गठित करने का प्रस्ताव किया गया था। यह भी घोषणा की गई थी कि मौद्रिक नीति की मध्य-त्रैमासिक समीक्षा जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च में की जाएगी। वर्ष 2009 से पॉलिंसी दरों में किए गए परिवर्तन सारणी 4.17 में दिखाए गए हैं।

त्रैमासिक समीक्षाएं

4.69 जैसाकि पहली त्रैमासिक समीक्षा में निर्णय लिया गया था, बृहत्-आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 दिसंबर, 2010 को सम्पन्न मध्य-त्रैमासिक समीक्षा में एलएएफ के तहत रेपो दर में 25 आधार बिन्दु की वृद्धि करके उसे 5.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.0 प्रतिशत करने और रिवर्स रेपो दर में 50 आधार बिन्दु की वृद्धि करके उसे 4.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.0 प्रतिशत करने का निर्णय लिया।

4.70 वर्ष 2010-11 की मौद्रिक नीति की दूसरी त्रैमासिक समीक्षा (2 नवंबर 2010 को जारी) में यह कहा गया था कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में पुनरुत्थान के नाजुक और असमान स्वरूप तथा अत्यधिक बेरोजगारी से वैश्विक पुनरुद्धार की स्थिरता

को लेकर चिंताएं उभरती हैं जबकि मुख्यतः घरेलू कारकों से संचालित भारतीय अर्थव्यवस्था प्रवृत्तिमूलक विकास दर के नजदीक चल रही थी। तथापि, हाल के महीनों में आई कुछ कमी के बावजूद, भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति अपनी मध्यावधि क प्रवृत्ति से काफी अधिक और आरबीआई के अपेक्षित स्तर से पर्याप्त ऊपर थी (सारणी 4.18)। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 नवंबर 2010 को रेपो दर में 25 आधार बिन्दु की और वृद्धि करके उसे 6.25 प्रतिशत और रिवर्स रेपो दर में 25 आधार बिन्दु की बढ़ोत्तरी करके उसे 5.25 प्रतिशत कर दिया। सीआरआर को बैंकों के एनडीटीएल के 6 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है।

4.71 भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की तीसरी त्रैमासिक समीक्षा (25 जनवरी 2011) में कहा कि इसका दृष्टिकोण चार महत्वपूर्ण तर्कों से निर्धारित होता है:

- साफ जाहिर है कि मुद्रास्फीति सबसे बड़ी चिन्ता है। मुद्रास्फीति की दर ऊंची तो बनी ही हुई है, मुद्रास्फीति की दिशा में हुआ उलटाव भी असाधारण रहा है। प्राथमिक खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति में पुनः तेजी से वृद्धि हुई है। खाद्य-भिन्न वस्तुओं की मुद्रास्फीति और ईंधन की मुद्रास्फीति पहले ही ऊंचे स्तर पर है। खाद्य-भिन्न विनिर्मित वस्तुओं की मुद्रास्फीति भी वृद्धि का रुख लिए रही है। खाद्य और ईंधन मूल्यों की वृद्धि के सामान्यीकृत मुद्रास्फीति में परिवर्तित हो जाने के संकेत हैं।
- दूसरा, वैश्विक वस्तु मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है जिससे घरेलू मुद्रास्फीति के बढ़ने का खतरा अधिक हो गया है।
- तीसरा, वैश्विक पुनरुत्थान के अनिश्चित रहते हुए भी विकास संकट-पूर्व के मार्ग पर करीब-करीब लौट आया है।
- चौथा, वैश्विक पुनरुत्थान से जुड़ी अनिश्चितता कम हो गई है।

सारणी 4.18 : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2010-11 के लिए वृहद पैरामीटरों के निर्देशात्मक अनुमान

	वृद्धि दरों हेतु निर्देशात्मक अनुमान (प्रतिशत)			
	वार्षिक नीति 2010-11 (20 अप्रैल 2010)	पहली तिमाही की समीक्षा (27 जुलाई 2010)	दूसरी तिमाही की समीक्षा (2 नवम्बर 2010)	तीसरी तिमाही की समीक्षा (25 जनवरी, 2011)
स.घ.उ. में वृद्धि	8.0	8.5	8.5	8.5
डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति	5.5**	6.0**	5.5	7.0
मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि (एम ₃)	17.0	17.0	17.0	17.0
समायोजित खाद्य-भिन्न ऋण	20.0	20.0	20.0	20.0

टिप्पणी : * इसमें एससीबी द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, निजी कारपोरेट क्षेत्र के बांड/डिबेंचर/शेयरों में और सीपी में किया गया निवेश शामिल है।

** पुरानी श्रृंखला।

4.72 मौजूदा बृहत्-आर्थिक स्थितियों के आकलन के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक दर को 6.0 प्रतिशत और अनुसूचित बैंकों के सीआरआर को उनके एनडीटीएल के 6.0 प्रतिशत कर रखा है; एलएएफ के अंतर्गत रेपो दर में 25 आधार बिन्दु की वृद्धि करके उसे 6.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया; और एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो दर में 25 आधार बिन्दु की बढ़ोतरी करके उसे 5.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया। नकदी की स्थिति के आकलन के आधार पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एलएएफ के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 8 अप्रैल, 2011 तक उनके एनडीटीएल के 1 प्रतिशत तक अतिरिक्त नकदी सहायता दी। यह सुविधा लेने के चलते, एसएलआर को बनाए रखने में होने वाली किसी कमी को पूरा करने के लिए बैंकों को पूर्णतः एक तदर्थ उपाय के तौर पर दाण्डक ब्याज की माफी लेने की अनुमति दी गई।

चुनौतियां और संभावनाएं

4.73 मुद्रास्फीति निःसंदेह सबसे बड़ी चिन्ता का मुद्दा है। अप्रैल-दिसंबर 2010-11 में 9.4 प्रतिशत के स्तर पर व्याप्त रही औसत हेडलाइन मुद्रास्फीति दशकीय औसत में अब तक सर्वाधिक रही है। यही बात प्राथमिक खाद्य वस्तुओं, ईंधन एवं विद्युत तथा विनिर्मित उत्पादों के लिए डब्ल्यूपीआई आधारित वार्षिक औसत मुद्रास्फीति के बारे में भी सच है। चालू वित्त वर्ष में, इस दर के असंतोषजनक ढंग से ऊंचे स्तर पर बने रहने पर भी, दिसंबर में मुद्रास्फीति की दिशा में हुआ उलटाव भी असाधारण रहा है। अगस्त और नवंबर 2010 के बीच मुद्रास्फीति में कुछ कमी हो जाने के बाद, दिसंबर 2010 में प्राथमिक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेज़ी से हुई वृद्धि और तेल की वैश्विक कीमतों में हाल में आए उछाल के कारण मुद्रास्फीति में फिर से बढ़ोतरी हो गई। खाद्य-भिन्न विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति में भी वृद्धि का रुख रहा है जो वृद्धिकारी मांग की स्थितियां दर्शाती हैं। लेकिन, हेडलाइन मुद्रास्फीति कम होकर जनवरी 2011 में 8.23 प्रतिशत के स्तर पर आ गई है और उम्मीद है कि यह रुख अगले दो महीनों में जारी रहेगा।

4.74 भविष्य की ओर देखें तो, मुद्रास्फीति से जुड़ी संभावनाएं अर्थव्यवस्था में खाद्य-मूल्य की स्थिति और मांग पक्ष के दबावों से निर्धारित होंगी। खाद्य-मुद्रास्फीति में वृद्धि न सिर्फ कुछ समय

से लगातार बनी हुई है बल्कि यह काफी तेज़ भी रही है। खाद्य वस्तुओं की उच्च मुद्रास्फीति सिर्फ भारत की ही विशेषता नहीं है, बल्कि यह कई अन्य देशों में भी बढ़ी है। खाद्य तेलों जैसी कुछ खाद्य मदों के आयात पर निर्भरता के चलते वैश्विक खाद्य कीमतों में वृद्धि हो जाने से घरेलू खाद्य मूल्य स्थिति बिगड़ सकती है। मौजूदा विकास और स्फीतिकारी रुझानों के कारण मुद्रास्फीतिरोधी मौद्रिक रुख को जारी रखना ज़रूरी हो गया है।

4.75 एक ऐसा माहौल, जहां ऋण की लागत और उपलब्धता विकास की रफ्तार में सहायक हो तथा साथ ही मुद्रास्फीति में कमी लाकर उसे वापस अधिक संतोषजनक लक्षित स्तरों तक लाना सुनिश्चित किया जा सके—ऐसा ही माहौल कायम करने का मुद्दा अल्पावधिक परिप्रेक्ष्य में नीतिगत विचार-प्रक्रिया का मुख्य मुद्दा होगा। इसे हाल ही के समय में बिलकुल ही अप्रत्याशित स्तर की मुद्रास्फीति, मूल्यों विशेषकर खाद्य मूल्यों की सापेक्ष वृद्धि के जारी रहने और अर्थव्यवस्था में व्यापक स्फीतिकारी संभावनाओं के सृजित होने के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जहां साथ-साथ अर्थव्यवस्था में मांग की प्रबंध-व्यवस्था करने और स्फीतिकारी दबावों को मंद करने के लिए मौद्रिक नीति के साधनों को भी सक्रियता से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन, साथ-साथ राजकोषीय घाटों का समेकन करना भी ज़रूरी होगा क्योंकि इससे निकट भविष्य में मौद्रिक नीति का सहज कारगर संचालन किए जाने की उम्मीद की जाती है। राजकोषीय घाटों के कम हो जाने से विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए अधिक ऋण उपलब्ध हो पाएगा, जबकि कठोर मौद्रिक नीति का असर स्फीतिकारी दबावों के कम होने में दिखाई देने लगता है। लेकिन मौद्रिक नीति का असर एक अन्तराल के बाद दिखाई देता है। अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव आंशिक रूप से आपूर्ति संबंधी अडचनों, विशेषकर खाद्य और अन्य प्राथमिक वस्तुओं की आपूर्ति संबंधी मुश्किलों के साथ-साथ खाद्य-मदों, तेल और अन्य वस्तुओं की ऊंची वैश्विक कीमतों के अन्तरण से भी पैदा होते हैं। इसलिए ये सब बातें अल्पावधिक परिप्रेक्ष्य में इस मुद्दे को पेचीदा बना रही हैं। यदि वस्तुओं के बाह्य नकारात्मक मूल्य संबंधी आघात और अधिक बढ़ गए तो यह उलझन और अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता के साथ-साथ विकास की रफ्तार को बनाए रखने की नीतिगत चुनौती मौद्रिक नीति और बृहत्-आर्थिक प्रबंधन का केंद्र बिन्दु होगी।